ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -39 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 28 मई से 03 जून (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने दिखाई रुचि

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगेः मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने लाना हमारा उद्देश्यः मुख्यमंत्री विष्णुदेव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी नई पहचान गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने, निवेश अनुकूल नीतियों और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण प्रदेश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अपने निवास कार्यालय में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में देश की प्रतिष्ठित इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक नैसर्गिक विरासत की अमूल्य धरा है, जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं और पर्यटकों के लिए बेहतर ठहराव, परिवहन तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से

छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में लगातार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और इसी क्रम में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई गई है, जो प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निवेश से पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

बैठक के दौरान इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के समक्ष अपने निवेश प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए और बताया कि कंपनी छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगभग 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की योजना पर कार्य कर रही है, जिसे शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस निवेश से प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। तथा सभी आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश के रास्ते व्यापक रूप से खुले हैं। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक अधोसंरचना, उच्चस्तरीय सुविधाओं और निवेश प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से विकसित करने की दिशा में विशेष पहल कर रही है। प्रदेश की बेहतर मानसूनी परिस्थितियां, समृद्ध प्राकृतिक संपदा और निवेश अनुकूल नीति पर्यटन विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही हैं।

बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने निवेश प्रोत्साहन नीति तथा उपलब्ध इंसेंटिव्स की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई निवेशक 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करता है अथवा 1000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, तो उसे 'बी-स्पोक पॉलिसी' के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाओं तथा पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, निवेश आयुक्त ऋतु सेन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग सचिव रजत कुमार, पर्यटन विभाग सचिव डॉ. एस. भारतीदासन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

समाचार सार

कम बारिश बढ़ा सकती है महंगाई; सरकार का दावा

नईदिल्ली। देशभर के ज्यादातर हिस्से इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में हैं। वहीं, इस साल अल-नीनो के चलते मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। अगर सामान्य से कम बारिश रहती है, तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। ग्रामीण मांग पर दबाव दिख सकता है। साथ ही आम कंज्यूमर को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, सरकार यह दावा कर रही है कि वह अल-नीनो के खतरे से निपटने के लिए तैयार है।

होर्मुज संकट से बढ़ी महंगाई की मार

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल, गैस और दूसरे ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से भारतीय उद्योगों की लागत तेजी से बढ़ रही है। इसका असर अब आम लोगों की जेब पर भी पड़ने की आशंका है। स्टील, प्लास्टिक, उर्वरक, रसायन, सिंथेटिक रबर और धातु उद्योगों में उत्पादन महंगा हो गया है।

एलआईसी का रियल एस्टेट संपत्तियों से बेहतर रिटर्न पाने का लक्ष्य

नईदिल्ली। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों से मिलने वाले यील्ड या रिटर्न को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित रही है। इसके साथ ही बीमा कंपनी 60,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अपनी विशाल संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अलग सब्सिडियरी कंपनी बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। एलआईसी के सीईओ एवं एमडी आर. दुरईस्वामी ने कहा, हमारे पास काफी रियल एस्टेट संपत्तियां हैं, जिनमें कुछ विरासत में मिली हैं और कुछ पिछले 70 वर्षों में खरीदी गई हैं।

देश के सात हवाई अड्डों पर शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेगा रोजगार, सेना ने किया समझौता

नई दिल्ली (ए)। देश के सात प्रमुख हवाई अड्डों पर शहीद सैनिकों के परिवारजनों को रोजगार दिया जाएगा। भारतीय सेना और एयर इंडिया लिमिटेड के बीच सैनिक परिवारों के कल्याण को लेकर यह समझौता हुआ है। यह समझौता सैनिक परिवारों के कल्याण और रोजगार देने के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। गुरुवार को सेना ने इस समझौता ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी साझा की।

स्कूलों में दी जाएगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग- इस समझौते के तहत सेना के 25 स्कूलों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए लैबोरेटरी भी स्थापित की जाएंगी। ये विशेष प्रकार की प्रयोगशालाएं होंगी जहां छात्रों को रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। सेना का कहना है कि यह साझेदारी रोजगार, सशक्तिकरण और पर्यावरण के तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इस समझौते का मूल उद्देश्य वीर नारियों तथा उनके परिवारों को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना और सैन्य समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। समझौते के तहत एयर इंडिया द्वारा वीर नारियों के लिए 20 तथा उनके बच्चों के लिए 40 रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

सेना की पहल से होंगे ये फायदे

इस पहल का उद्देश्य शहीद सैनिकों के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, सेना द्वारा संचालित 25 आशा स्कूलों में आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे भविष्य में बेहतर करियर अवसर प्राप्त कर सकें। पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सेना के अस्पतालों में बैटरी से चलने वाली ई-कार्ट भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

भारत-अमेरिका संबंधः NYT ने लिखा-

रूबियो का दौरा पेनकिलर जैसा, लेकिन रिश्ते सुधारने के लिए असली दवा की जरूरत

नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया, इसका मुख्य मकसद इस दक्षिण एशियाई दिग्गज देश को यह भरोसा दिलाना था कि वह अभी भी अमेरिका पर निर्भर रह सकता है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि यह दौरा ट्रंप प्रशासन की व्यापार, आव्रजन (इमिग्रेशन) और ईरान युद्ध से जुड़ी नीतियों के कारण लगे गहरे घावों पर महज एक मरहम या पेनकिलर की तरह है। इस बहुचर्चित दौरे से भारत को कूटनीतिक स्तर पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है।

असली दवा की दरकार और ऊर्जा संकट का दबाव- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के विशेषज्ञ डॉ. कॉन्स्टेंटिनो जेवियर के अनुसार, यह दौरा एक अच्छे पेनकिलर की तरह था, लेकिन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ असली दवा की जरूरत है। यह असली दवा दोनों देशों के नेताओं के बीच एक मौलिक राजनीतिक रीसेट, ट्रंप के भारत दौरे या व्यापार और रक्षा सौदों में किसी बड़ी सफलता के रूप में हो सकती है। भारत अपनी कच्चे तेल की 90 प्रतिशत जरूरतें आयात से पूरी करता है। ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत की तेल तक पहुंच काफी कम हो गई, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) करने की अपील करनी पड़ी। इससे पहले अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25त्न दंडात्मक टैरिफ लगा दिया था, जिसे भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद सीमित करने पर सहमति जताने के बाद फरवरी में हटा लिया गया।

नीतियों में निरंतरता की कमी और चीन का फैक्टर- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विपरीत ट्रंप का भारत के प्रति रवैया अस्थिर (ब्लो-हॉट, ब्लो-कोल्ड) रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष वी. पंत के मुताबिक, मुख्य समस्या ट्रंप प्रशासन की नीतियों में निरंतरता की कमी और इस रिश्ते के प्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता का अभाव है, जिससे भारत के पास जुड़ाव का कोई ठोस ढांचा नहीं बचा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की हालिया मुलाकात ने भी भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। डॉ. जेवियर का कहना है कि भारत को डर है कि अमेरिका-चीन संबंध स्थिर होने पर उसकी उपयोगिता कम हो सकती है और वह महज अमेरिका का एक बैकअप प्लान बनकर रह सकता है।

दावों और हकीकत में अंतरः अपने दौरे के दौरान रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे रणनीतिक भागीदारों में से एक बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नई दिल्ली के एक रिसेप्शन में फोन पर जुड़कर पीएम मोदी को अपना बेहतरीन मित्र कहा और दावा किया कि भारत जो चाहता है, उसे मिलता है। हालांकि, हकीकत इसके उलट नजर आती है; ट्रंप प्रशासन की आव्रजन पाबंदियों ने भारतीय छात्रों और कामगारों को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूबियो ने इन नीतियों का यह कहकर बचाव किया कि ये विशेष रूप से भारतीयों को लक्षित नहीं हैं।

दौरे के मुख्य नतीजे और आगे की राह

खनिज समझौताः दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने पर मिलकर काम करने से जुड़े एक समझौते की रुपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं।

व्यापार वार्ताः भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि व्यापार वार्ता के अगले दौर के लिए एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही भारत का दौरा करेगा।

क्वाड पर अनिश्चितताः रूबियो के दौरे का अंतिम दिन क्वाड देशों (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की समुद्री सुरक्षा और वाणिज्य पर केंद्रित रहा। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि चीन पर ट्रंप के फोकस को देखते हुए क्वाड में अमेरिका की सक्रियता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

मुख्यमंत्री विजय का दिल्ली दौरा संपन्न

नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपनी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा पूरी करने के बाद गुरुवार को चेन्नई लौट आए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात नहीं की।

कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने कहा कि उनके पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मुख्यमंत्री की यह यात्रा केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित थी, राजनीतिक बैठकों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात रद्द नहीं हुई है, बल्कि फिलहाल टाल दी गई है। तिलक ने पत्रकारों से कहा, मुख्यमंत्री 11 जून के आसपास नीति आयोग की बैठक के लिए फिर दिल्ली आ सकते हैं। और तब राहुल व सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। विजय ने अपनी दिल्ली यात्रा समाप्त की और विशेष विमान से चेन्नई लौट गए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इनमें मेकेदातु बांध विवाद, मछुआरों की गिरफ्तारी और तमिल वंदना गीत को लेकर विवाद शामिल थे।

त्विषा शर्मा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह गिरफ्तार

भोपाल। राजधानी भोपाल की हाईप्रोफाइल त्विषा शर्मा केस में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को भोपाल पुलिस ने सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार और बुधवार को लगातार कई घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। गुरुवार सुबह नई दिल्ली से सीबीआई की आधा दर्जन महिला पुलिसकर्मियों-अधिकारियों के भोपाल पहुंचने के बाद गिरफ्तारी की पटकथा लिखी गई। तकरीबन शाम 6 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह का मेडिकल कराने भोपाल एम्स ले जाने के लिए घर से निकली है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक दिन पहले गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद की गई। त्विषा शर्मा की 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। गिरिबाला सिंह ने घटना के दो दिन बाद भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 15 मई को उनकी उम्र और मृतका को किए गए पैसों के ट्रांसफर का हवाला देते हुए जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने बुधवार को 17 पन्नों के आदेश में इस जमानत को निरस्त कर दिया।

गुरुवार सुबह दस बजे सीबीआई की विशेष टीम महिला पुलिसकर्मियों के साथ बागमुगालिया एक्सटेंशन स्थित गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। समर्थ सिंह को भी लेकर सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के यहां गई थी। दोनों को कुछ देर तक आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई, इसके बाद एक टीम समर्थ सिंह को लेकर विशेष स्थान पर चली गई। भोपाल पुलिस के सूत्रों के अनुसार सुबह दस बजे से तीन बजे तक की पूछताछ के बाद ही सीबीआई गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की पटकथा तैयार कर ली थी।

तीन बजे भोपाल पुलिस आयुक्त को सूचना देकर सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के घर के बाहर विशेष सुरक्षा टीम तैनात करने की मांग की थी। इसके बाद आनन-फानन में बागसेवनिया, मिसरोद और कटारा हिल्स थाने के पुलिसकर्मियों के साथ भारी पुलिस बल गिरिबाला सिंह के बाहर सुरक्षा में बैरिकेडिंग्स कर तैनात किया गया।

यह भारत का दशक है, वैश्विक चुनौतियां नए सिरे से सोचने का मौकाः मुकेश अंबानी

नईदिल्ली (ए)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने वित्तीय वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में कई अहम बातों का खुलासा किया है। उन्होंने दुनिया भर में हो रहे बदलावों को भारत के लिए एक नए अवसर के रूप में देखने की वकालत की है। इसके साथ ही, एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए रिलायंस वित्त वर्ष 2026 में 10 अरब डॉलर का सालाना शुद्ध मुनाफा कमाने

वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। मौजूदा समय में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18.26 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। मुकेश अंबानी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में वैश्विक उद्योग पीढ़ियों में होने वाले सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस दौर को परेशानी का नाम देने के बजाय इसे नई संभावनाओं के रूप में देखा है। उनके अनुसार, उद्योगों, तकनीक और देशों के बीच की सीमाएं अब नए सिरे से तय की जा रही हैं। अंबानी ने बताया कि ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी बदलाव हो रहा है, ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन तेज हो गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व डेटा का तेजी से बढ़ता उपयोग आधुनिक दुनिया का पूरा ढांचा बदल रहा है।

इलाज में देरी की वजह से बच्चे की मौत

डीजल की कमी से गर्भवती महिला के लिए नहीं पहुंच पाई एंबुलेंस

मुंबई (ए)। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया है कि सरकारी एम्बुलेंस समय पर न मिलने और कथित तौर पर डीजल की कमी के कारण गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई।

परिजनों के अनुसार, महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद उन्होंने 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं पर संपर्क किया। आरोप है कि करीब दो घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली और स्टाफ ने यह कहकर मदद देने से इनकार कर दिया कि

वाहन में डीजल नहीं है। परिवार का कहना है कि जब हालत बिगड़ती गई तो उन्होंने किसी तरह पैसे जुटाकर निजी वाहन की व्यवस्था की और महिला को सरकारी मेडिकल कॉलेज, हिंगोली पहुंचाया।

परिजनों ने दावा किया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने सिजेरियन डिलीवरी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और नवजात को बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा जा रहा है।

महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल आरोपों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई लापरवाही हुई है तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू

इबोला संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट

रायपुर। वैश्विक स्तर पर इबोला वायरस के बढ़ती चिंता के बीच छत्तीसगढ़ भी अलर्ट मोड पर आ चुका है. रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग ने इबोला जांच काउंटर बनाया है. जहां बाहरी राज्यों और अंतराष्ट्रीय यात्रियों की अनिवार्य जांच शुरू कर दी गई है. स्कैनिंग मशीन से जांच के साथ ही ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच जारी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके. अभी तक भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है. हालांकि एहतियाती तौर पर पूरी तरह सतर्क हैं. छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने इबोला संक्रमण को लेकर रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. यात्रियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है. आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है. संदिग्ध लक्षण वाले यात्रियों को आइसोलेशन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किया गया है. अफ्रिका के कांगो और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न' घोषित है. इसी के बाद से दुनियार के देशों ने

सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. केंद्र सरकार लगातार इबोला वायरस में खतरे को लेकर एतिहायत बरत रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में जानकारी दी थी कि फिलहाल भारत में इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है. देशभर में एयरपोर्ट, बंदरगाह और सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है. NDC, ICMR और अन्य एजेंसियों को ट्रैकिंग, टेस्टिंग और सर्विलांस के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इबोला एक बेहद गंभीर और जानलेवा वायरल बीमारी है, जिसकी मृत्यु दर काफी अधिक मानी जाती है. यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति या जानवर के खून और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है. इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, उल्टी और दस्त शामिल हैं. गंभीर स्थिति में मरीज को आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है. इस बीमारी का ऊष्मायन काल आमतौर पर 2 से 21 दिनों के बीच होता है।

पत्रकार आनंद साहू ने दिया ईमानदारी का मिसाल

30 लाख रुपए के सोना-चांदी का आभूषण सहित नगद 38 हजार रुपए थाना में किया जमा

बेमेतरा। वर्तमान दौर में जहां लोग छोटी बड़े चीजों को भी लालच में आकर कब गबन कर जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। वहीं बेमेतरा जिला मुख्यालय के पत्रकार आनंद साहु ने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और नैतिकता मूल्यों का परिचय देते हुए मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश किया। सिटी प्रेस क्लब बेमेतरा के सचिव आनंद साहु को 27 मई को प्रातः लगभग साढ़े चार बजे एक लावारिस हालत में एक लेदर का बैग मिला। बैग की जांच करने पर उसमें करीब 30 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण एवं लगभग 38 हजार रुपये नगद पाए गए। इतनी बड़ी रकम और कीमती सामान मिलने के बावजूद आनंद साहु ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बिना किसी देर किए उक्त बैग को तत्काल सिटी कोतवाली थाना बेमेतरा में सुरक्षित जमा करा दिया। आनंद साहु के इस सराहनीय कार्य की पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है। लोगों का कहना है कि आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। उनका यह कदम समाज के लिए प्रेरणादायक संदेश है कि सच्चाई और ईमानदारी जिंदा है। सिटी प्रेस क्लब सहित सामाजिक संगठनों, पत्रकार साथियों एवं नगरवासियों ने आनंद साहु को उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हार बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

क्या-क्या था बैग में

थाना में बैक को सुपुर्द करने के बाद बैग को खोला गया, जिसमें कुल नगदी रकम 37150 था। इसके अलावा 8 नग पतला पत्ती, सोने का 9 नग ताबीज, 4 नग सोने का पट्टी, आठ नग भगवान वाले पत्ती सोने का, एक नग पेंडल सोने का, 16 नग कान का टॉप्स सोने का, 14 नग चांदी का सिक्क । छोटा बड़ा था सोने के आभुषणों का वजन लगभग 200 ग्राम बताया गया है।

कारीगर भूल गया था बैग को दुकान के बाहर

इस संबंध में विजय कुमार सोनी पिता नंदकुमार सोनी गोविंद विहार निवासी बेमेतरा ने लिखित में सिटी कोतवाली पुलिस थाना में लिखित में बताया कि वह सोने चांदी के कारीगरी का काम करता है बीते 26 मई को दिन मंगलवार को रात 9:00 बजे कत्था रंग एक लेदर बैग अपने रकम तथा सोने के सामान सहित अशोक मोटर्स दुकान के बाहर रखकर भूल गया था। इस संबंध में कोतवाली पुलिस थाना के टीआई सोनम ग्वाला द्वारा पूछताछ एवं जांच किया गया। उसके बाद नगद राशि सहित सोने चांदी के गहना को एसडीओपी भुषण एक्क । के उपस्थिति में विजय कुमार सोनी को सौंपा गया।

डीआईजी साहु ने किया सम्मान

शाम को डीआईजी रामकृष्ण साहु पत्रकार आनंद साहु गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करते हुए बधाई दिया और शुभकामनाएं व्यक्त किए। इस अवसर पर सिटी प्रेस क्लब बेमेतरा अध्यक्ष दिनेश दुबे, सर्राफ एसोशिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा विजय सोनी, श्रीराम देवांगन, बिट्टल सोनी, अशोक सोनी रामगोपाल साहु सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

कांग्रेस भवन बेमेतरा में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने दी श्रद्धांजलि

बेमेतरा। बेमेतरा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के शिल्पकार जवाहर लाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज पुराना कांग्रेस भवन, भारत माता चौक बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने पंडित नेहरू के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी एवं उनके विचारों एवं योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा जी ने कहा कि, देश निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आधुनिक भारत की नींव रखने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने देश को वैज्ञानिक सोच, औद्योगिक विकास, शिक्षा एवं लोकतंत्र की मजबूत दिशा प्रदान की। उनके आदर्श एवं विचार देशवासियों को प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक कांग्रेस सहित कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों एवं पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने पंडित नेहरू जी के बताए मार्ग पर चलकर देशहित एवं जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगत साहू मिथलेश वर्मा रश्मि मिश्रा रीता पांडे जनता साहू शकुंतला साहू हेमिन यादव राजू साहू सुमन गोस्वामी ललित विश्वकर्मा शिव वर्मा नारायण छाबड़ा मनोज शर्मा प्रतीक दुबे अजय राज सेन चितरेन वर्मा प्रकाश ठाकुर रवि रजक बलवंत साहू राजेश नवरंगे खूबचंद चंद्राकर भीखम साहू घनश्याम देवांगन सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामुहिक विवाह में बेमेतरा के विधायक करेंगे विवाह

बेमेतरा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामुहिक विवाह में बेमेतरा के विधायक दीपेश साहु एक आम जन की तरह विवाह करेंगे बेमेतरा में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को आम जन तक पहचान बनाने के लिए बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुऐ अनुकरणीय पहल करते हुए इसी योजना के तहत स्वयं विवाह करने का निर्णय लिया है। जो आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही विधायक के इस निर्णय की पूरे जिले सहित प्रदेशभर में जमकर चर्चा हो रही है। विधायक दीपेश साहु ने तरुणा साहु के साथ विवाह आगामी 31 मई को नगर के बेसिक स्कूल मैदान में भव्य सामूहिक विवाह समारोह में करेंगे, जहां विधायक दीपेश साहू सहित कुल 24 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक दीपेश साहू का यह कदम समाज में सादगीपूर्ण विवाह, फिजूलखर्ची पर रोक और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आमतौर पर जनप्रतिनिधियों के भव्य आयोजनों के बीच विधायक का यह निर्णय जनता के बीच सकारात्मक संदेश दे रहा है। इस सामुहिक विवाह सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु सायं विधानसभा अध्यक्ष रमण सिंह सहित कई कैबिनेट मंत्री आने की संभावना है इस लिए इस कार्यक्रम को वृहद स्तर पर मनाने की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में इस पहल को जनप्रतिनिधि द्वारा जनता की योजना को खुद अपनाने की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को नई पहचान मिलेगी और जरूरतमंद परिवारों को भी प्रेरणा मिलेगी। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रहने की संभावना है। पूरे आयोजन को भव्य एवं यादगार बनाने जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

विधायक निधि के कार्य में ठेकेदार की मनमानी प्लिंथ लेवल का कार्य, संपूर्ण राशि का आहरण

नगर पंचायत डोंगरगांव में ठेकेदारों का दबदबा कायम

डोंगरगांव नगर। नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड 9 करियाटोला स्थित माड़िया देव परिसर में स्वीकृत बाउंड्री वॉल निर्माण में ठेकेदार की मनमानी व नगर पंचायत की लापरवाही उभरकर सामने आई है। ठेकेदार द्वारा बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य में सिर्फ प्लिंथ लेवल का कार्य करके विधायक निधि की संपूर्ण राशि आहरित कर लिया है। इस वाकये की जानकारी होने के बाद स्थानीय नागरिकों ने निर्माण में अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो विधायक निधि से वर्ष 2023-24 में लगभग 5 लाख रुपये की लागत से 225 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर केवल कुछ हिस्सों में प्लिंथ लेवल डालकर बाकी लगभग 90 फीसदी कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जबकि ताजा जानकारी मुताबिक उक्त कार्य के एवज में विधायक निधि की संपूर्ण राशि आहरित कर लिया है। आलम ये है कि स्वीकृति के 2 वर्षों के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

जांच व कार्रवाई की मांग

नगर पंचायत के वार्ड 9 के नागरिकों ने विधायक निधि की शासकीय राशि की बंदरबाट का आरोप लगाते हुए अधूरे कार्य कर संपूर्ण राशि के आहरण को नियम विरुद्ध बताते हुए नगर पंचायत प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नागरिकों ने अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग भी की है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

ठेकेदार पर लगे गंभीर आरोप

सूत्रों की माने तो ठेकेदार राहुल सिंह उर्फ राहुल बिहारी द्वारा प्लिंथ लेवल कार्य कर संपूर्ण राशि आहरण कर लेने शेष राशि का उपयोग दूसरी जगह करने की बात कहने पर वार्ड में आक्रोश निर्मित हो गया है। वार्डवासियों ने ठेकेदार की मनमानी कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि इस कार्य को लेकर नागरिक नगर पंचायत की भी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।

मुस्लिम समाज ने मनायाईद उल अजहा का त्यौहार

दल्लीराजहरा। जामा मस्जिद दल्लीराजहरा के सदर (अध्यक्ष) मुश्ताक अहमद अंसारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गुरुवार को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। जामा मस्जिद दल्ली राजहरा के ईमाम हाफिज अब्दुल बशीर ने नमाज से पहले खिताब किया और बताया कि कुर्बानी का मकसद अल्लाह की नज़दीकी हासिल करना है। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद अंसारी ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे जिस मौजु पर इजहारे ख्याल करने का मौका मिला है वो है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा मुसलमानों की दूसरी बड़ी मजहबी ईद है जिसे हम कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। यह ईद हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। इस्लाम एक मुक्कमल जाबताए हयात है जो हमें मोहब्बत, भाईचारे, इसार और कुर्बानी का हुक्म देता है। अल्लाह ताअला ने हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी खुशी खुशी अल्लाह की रजा पर राजी होने का ऐलान किया। जब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह तअला ने उनकी इस अज़ीम अताअत और कुर्बानी को कुबूल फ़रमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। यही वो अज़ीम वाक्या है जिसकी याद में हर साल मुस्लमान ईद उल अजहा का त्यौहार मनाते हैं। सदर मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि ईद उल अजहा सिर्फ जानवर जबहा करने का नाम नहीं है। बल्कि यह हमें अपनी ख्वाहिशों, गुरूर, हसद और बुराईयों को कुर्बानी करने का संदेश देती है। अगर इंसान सिर्फ जानवर कुर्बान करें मगर अपने अंदर की बुराईयों को खत्म ना करें तो कुर्बानी का असल मकसद हासिल नहीं होता है। ईद उल अजहा हमें गरीबों और जरुरतमंदों का ख्याल रखने की भी तामील देती है। कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों को तकसीम किया जाता है ताकें वो भी ईद की खुशीयों में शरीक हों सकें। इस्लाम मुहब्बत, अमन और इंसानियत का मजहब है और यही पैगाम हमें ईद उल अजहा हमें देती है। इस मुबारक दिन नमाजे ईद उल अजहा अदा करतें हैं एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और खुशियां बांटते हैं। सदर मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि हमारा मुआशरा नफरत, खुदगर्जी जैसे मसाइल का शिकार है अगर हम ईद उल अजहा के हकीकी पैगाम को समझ लें तो तो हमारा मुआशरा मोहब्बत, अमन और भाईचारे का का गहवास बन सकता है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी ना दे बल्कि अपनी बुरी आदतों, झूठ, हसद, लालच और नफरत को भी कुर्बान करें। अंत में सदर मुश्ताक अहमद ने मुस्लिम जमात को कहा कि ईद उल अजहा हमें अल्लाह की अताअत, कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देती है।

डाइट बेमेतरा में डीएलएड की वार्षिक परीक्षाएं शुरू, परीक्षा के पहले ही दिन मंडल सदस्य और जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण

पहले ही दिन परीक्षा में सभी 97 छात्राध्यापक उपस्थित

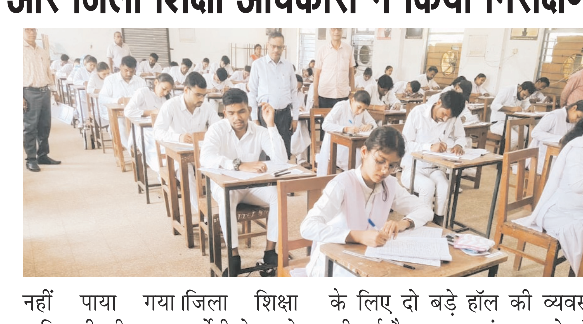

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित डीएलएड की वार्षिक परीक्षाएं डाइट बेमेतरा में प्रारंभ हो गई है। पहले दिन डीएलएड प्रथम वर्ष का 'बाल विकास और सीखना' विषय की परीक्षा की आयोजित हुई। प्रारंभ हुई इस परीक्षा में प्रथम वर्ष के सभी 97 छात्र अध्यापक शामिल हुए।

कोई भी परीक्षार्थी अनुपस्थित नहीं रहा। परीक्षा के आज पहले ही दिन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य जितेन्द्र सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी जी आर चतुर्वेदी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित पाया गया। परीक्षा का समय प्रात: 9 बजे से दोपहर 12.15 तक हैं। नकल या अनुचित साधन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया।जिला शिक्षा अधिकारी जी आर चतुर्वेदी ने पहले ही दिन डीएलएड के सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डीएलएड की वार्षिक परीक्षा के लिए सेजेस शिवलाल राठी विद्यालय बेमेतरा के प्राचार्य रामकुमार डड्सेना को केंद्राध्यक्ष बनाया गया है। जबकि डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता अनिल कुमार सोनी को सहायक केंद्राध्यक्ष बनाया गया है। कार्यालयीन सहयोगी की जिम्मेदारी सत्येंद्र मिश्रा सहायक ग्रेड2 संभाल रहे है। डीएलएड परीक्षा के लिए दो बड़े हॉल की व्यवस्था की गई है। कक्ष क्रमांक 1 बड़े हॉल में 60 परीक्षार्थियों के तथा छोटे हाल क्रमांक 2 में 37 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई ह। हॉल क्रमांक 1 में चार पर्यवेक्षकों की, जबकि हॉल क्रमांक 2 में तीन पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। पर्यवेक्षक के रूप में डाइट के सहायक प्राध्यापक परस राम साहू, डाइट व्याख्याता थलज कुमार साहू, शिक्षक मोहन कुमार साहू, कविता सेन, ज्योति देवांगन, पदमा निर्मलकर, दिनेश मानिकपुरी की ड्यूटी लगाई गई।

दल्ली पालिका में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर कार्यशाला आयोजित

दल्ली राजहरा। नगर पालिका दल्ली राजहरा में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उददेश्य से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष तोरण लाल साहू की उपस्थिति में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लागू किये गए नये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त जनप्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गई। नए नियम के तहत अब 2 तरह के कचरे (गीला, सूखा) की जगह 4 तरह का कचरा (गीला, सूखा, सेनेटरी, स्पेशल केयर) पृथक्करण एवं संग्रहण, बल्क वेस्ट जनरेटर की सक्रीय भागीदारी, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के डिजिटल पोर्टल, शिकायत निवारण प्रणाली, सफाई मित्र सुरक्षा, नागरिक सहभागिता, व्यापक जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन जैसे स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता, स्वच्छाग्रहियों का चयन, डिजिटल आईईसी, स्वच्छता श्रमदान आदि के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण के विभिन्न बिंदुओं के संबंध में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं दायित्वों पर विस्तार से चर्चा किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीमा बक्शी ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावशील हो चुका है। कार्यक्रम का उददेश्य कचरा प्रबंधन की वैज्ञानिक व्यवस्था को मजबूत करना, अपशिष्ट का स्थायी निपटान सुरक्षित करना एवं नागरिकों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी के साथ मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नपा उपाध्यक्ष मनोज कुमार दुबे, पार्षद सुरेश जायसवाल, मेवालाल पटेल, भूपेंद्र श्रीवास, टी.ज्योति, तरुण साहू, प्रदीप बाघ, रेखा सहारे, अरुणा रामटेके, पूनम सोरी, मोनिका, अनीता बाई, कार्यपालन अभियंता नित्यानंद उपाध्याय, जिला समन्वयक विक्रांत साहू, स्वच्छता प्रभारी सतीश चंद्राकर, स्टोर प्रभारी पंकज चंद्राकर, निकाय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नगर पालिका के उदासीन रवैये को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन

दल्लीराजहरा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दल्ली राजहरा के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा जनहित के कार्यो योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने में नगर पालिका द्वारा लगातार बढ़ती जा रही उदासीनता के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए मांगो का समाधान शीघ्र ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। शासन के द्वारा चलाए जा रही योजनाएं जिनमें प्रमुख रूप से श्रद्धांजलि योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, विधवा/ परित्यक्ता पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, जैसी समस्त योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पिछले 1 वर्ष से नहीं मिल पा रहा है इन योजनाओं के हितग्राही इस भरी दोपहरी के चिलचिलाती धूप में अपने-अपने संबंधित बैंकों का प्रतिदिन चक्कर काटते हैं और बैंक के द्वारा उन्हें एक ही जवाब दे दिया जाता है कि उनका पेंशन का राशि अभी नहीं आया है। नगर पालिका के चक्कर लगाने से भी कोई बताने को तैयार नहीं है कि उनकी पेंशन की राशि कब तक आएगी। प्रभावित हितग्राहियों ने कांग्रेस पार्षदों से संपर्क करके अपनी समस्या बताई। पार्षदों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पास अपनी बातें रखी और कांग्रेसजनो ने मिलकर इन हितग्राहियों को उनका लाभ दिलाने के लिए पहला कदम उठाते हुए नगर पालिका के जिम्मेदार पदाधिकारी के पास जाकर एक मांग पत्र सौंपा है। जिसमें यह सभी लाभकारी योजनाओं को शीघ्र ही पूरा करने की मांग की गई है यदि दिए समयावधि में नगर पालिका के द्वारा पेंशन की राशि का भुगतान हितग्राहियों के खाते में नहीं आने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दल्ली राजहरा नगर पालिका का घेराव करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतिराम कोसमा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष रवि जायसवाल, पार्षद रोशन पटेल, सूरज विभार प्राची सिंन्हा, ईश्वर राव, कृष्णा यादव हीरालाल पवार राकेश जायसवाल कुलदीप नोनहारे नितेश बामेश्वर चंदु सिन्हा उपस्थित रहे।

शासकीय भूमि पर हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य

बेमेतरा। जनपद पंचायत साजा अंतर्गत ग्राम पंचायत खुरूसबोड़ (आर.) में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में हितग्राही गणेश वर्मा पिता टेकसिंह के नाम आवास स्वीकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त की राशि 40 हजार रुपए दिनांक 01 नवंबर 2025 को हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत स्थल पर ही आवास निर्माण सुनिश्चित करने हेतु लगातार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत स्थल पर वर्तमान में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके विपरीत अन्य शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिस पर पंचायत एवं राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायत खुरूसबोड़ (आर.) द्वारा हितग्राही को कई बार मौखिक एवं प्रत्यक्ष रूप से समझाइश दी गई कि निर्माण कार्य केवल स्वीकृत स्थल पर ही किया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा तीन बार लिखित नोटिस भी जारी किए गए। संबंधित तहसीलदार द्वारा भी निर्माण कार्य पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई है। निर्धारित स्थल पर समय-सीमा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण राशि वसूली संबंधी प्रकरण न्यायालय अनुभागीय अधिकारी साजा को प्रेषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार लाभ दिलाने हेतु सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी जानकारी के संबंध में अधिकृत स्त्रोतों से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करें।

पेयजल समस्या दुरुस्त करने पीएचई को निर्देश निकाय सभागार में निकाय व पीएचई की बैठक

डोंगरगांव नगर। नगर में पेयजल की सुचारू व्यवस्था को लेकर 25 मई को निकाय के पदाधिकारियों एवं पीएचई विभाग के नुमाइंदों की विशेष बैठक आहुत हुई। नगर पंचायत अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी के अगुवाई में आहुत बैठक में पीएचई विभाग को नगर में सुव्यवस्थित तौर से जल प्रदाय हेतु शीघ्र कदम उठाने निर्देशित किया गया। बैठक में वार्ड क्रमांक 01 मोंगरा कालोनी में पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य कराये जाने, निकाय क्षेत्र में स्थित जल सप्लाई वाल्व को चेक कराने, पेयजल समस्या से ग्रसित वार्ड क्रमांक 04, 11 एवं 12 के पाईप लाईन चोक होने की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। चर्चा के दौरान वार्ड पदाधिकारीगण अपने वार्डो की समस्या से परिषद को अवगत कराते हुए पेयजल की समस्या का समाधान शीघ्र कराने की बात कही है। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंजू त्रिपाठी ने पीएचई विभाग के अधिकारी को दूरभाष के माध्यम से इस समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ठ कराते हुए जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था को दूरूस्त करने कहा। इस संबंध में कलेक्टर से प्रत्यक्ष मिलकर समस्या के संबंध में निवेदन पत्र प्रस्तुत कर जल्द से जल्द उचित निराकरण हेतु अपील की है। परिषद की विशेष बैठक में निकाय अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनम्र जेमा, उप अभियंता केआर बर्मन, सभापति पुरुषोत्तम साहू, पार्षदगण पद्मिनी ठाकुर, निर्मला मालेकर, गायत्री यादव, लक्ष्मीनारायण सेन, दुर्गेश रामटेके, कोमल साहू, सद्दाम खत्री, प्रफुल्ल जैन के अलावा पीएचई विभाग से सहायक अभियंता विनोद सिंह, उपअभियंता रूखमणी एवं निकाय के पेयजल प्रभारी छन्नूराम साहू उपस्थित थे।

कवर्धा को मिली नई सौगात, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया मित्र मिलन चौपाटी का लोकार्पण

फुटकर व्यापारियों को मिला स्थायी व्यवसाय का ठिकाना, शहरवासियों को अब एक ही जगह मिलेगा स्वाद का आनंद

कवधा। शहरवासियों को बड़ी सौगात देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा के हृदय स्थल में नवनिर्मित मित्र मिलन चौपाटी का भव्य लोकार्पण किया। इस नई चौपाटी के शुरू होने से अब शहरवासियों को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। यह स्थल खानपान के साथ-साथ परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के लिए भी आकर्षक केंद्र बनेगा। चौपाटी में रंग-रोगन, सजावट, आकर्षक रंग-बिरंगी लाइट, पार्किंग, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मित्र मिलन चौपाटी शहरवासियों और परिवारों के लिए एक बेहतर स्थल बनने जा रहा है, जहां लोग अपने परिवार के साथ आकर

स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो छोटे व्यवसायी पहले सड़क, चौक-चौराहों पर गुमटी लगाकर व्यवसाय करते थे, उन्हें अब स्थायी स्थान उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनका रोजगार भी सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि कवर्धा शहर तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शहर में वीर स्तंभ चौक, शिवाजी चौक, भोजली तालाब पाथवे चौड़ीकरण, हनुमंत वाटिका, ठाकुरदेव चौक से बस स्टैंड तक पहुंचने का मार्ग जैसे कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शिव वाटिका, मेडिकल कॉलेज और नालंदा लाइब्रेरी सहित कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और इसके प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो नियमित निरीक्षण कर रही है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भी अलग टीम निगरानी कर रही है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि शहर की सुरक्षा, स्वच्छता और बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर पालिका के सामने भी जल्द नई चौपाटी शुरू की जाएगी। इसके अलावा सियान सदन का निर्माण किया जाएगा, जहां बुजुर्गों के लिए आने-जाने और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम ऑफिस और शुगर फैक्ट्री परिसर में बलराम सदन और किसान सदन का निर्माण किया गया है। बाईपास को जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से गौरव पथ बनाया जा रहा है। नालंदा लाइब्रेरी, बूढ़ा महादेव परिसर उन्नयन, विशाल डोम निर्माण, मां विंध्यवासिनी मंदिर विस्तार और पुराने अस्पताल परिसर के उन्नयन जैसे कई विकास कार्य शहर में जारी हैं। साथ ही शहर को धूल रहित और स्वच्छ बनाने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भोरमदेव विद्यापीठ में युवाओं को निःशुल्क पीएससी और व्यापम की तैयारी कराई जा रही है, वहीं जिले के 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं। उन्होंने लोगों से मित्र मिलन चौपाटी का प्रचार-प्रसार करने और इसकी लोकेशन सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि कवर्धा वासियों का वर्षों पुराना इंतजार आज पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि चौपाटी में व्यापारियों को स्थायी स्थान दिया गया है, जिससे फुटकर व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही इससे शहर की यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि पानी, शौचालय, लाइट और पार्किंग जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि कवर्धा को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और मित्र मिलन चौपाटी इसी विकास यात्रा की एक नई सौगात है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष गणेश तिवारी, नगर पालिका उपाध्यक्ष पवन जायसवाल सहित पार्षद और बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे।

आतरगांव में चल रही है समानांतर सरकार, रेत उत्खनन के लिए नदी के सौदा की चर्चा

आतरगांव में 26 हजार देकर नदी का सीना चीर रहे माफिया?

डोंगरगांव नगर। अंचल के गांवों में समान्तर सरकार कोई नई बात तो नहीं है, बनिस्बत अवैध कृत्य कर शासन प्रशासन को चुनौती दी जा रही है। अनुभाग मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित आतरगांव में इन दिनों रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। हैरत की बात तो ये है कि खनिज माफिया गाँव का ही निवासी बताया जा रहा है। अनुभाग के ग्राम आतरगांव में नियमों को ताक पर रखकर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। नदी से अनियंत्रित तौर से रेत निकाली जा रही है। नाम नहीं छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि एक माफिया ने ट्रैक्टर वाहन मालिकों की टीम बनाकर गांव के एक गुट को 26 हजार रकम देकर नदी से रेत निकालने की तथाकथित स्वीकृति हासिल की है। इसके बाद से दिन रात रेत निकासी की जा रही है। आलम ये है कि रेत माफिया था संबंधित गुट द्वारा शासन को देय राजस्व की भी चिंता नहीं करते हुए गांव में अवैध कृत्य के लिए समांतर सरकार चलाई जा रही है। सूत्रों की माने तो आतरगांव में लगभग 6 ट्रैक्टरों से नियमित रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। इस पूरे मामले में गांव की एक स्थानीय समिति की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि कथित तौर पर प्रति ट्रिप राशि लेकर इस अवैध परिवहन को मौन सहमति दी जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों में इसे लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्राम के कुछ जागरूक ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए नदी को ही बेचने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की प्राकृतिक संपदा का खुलेआम दोहन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग मूकदर्शक बने हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।

ग्राम पंचायत की भूमिका संदिग्ध

इस मामले को लेकर सरपंच पति डामन साहू ने मीडिया को बताया कि पंचायत की ओर से रेत उत्खनन या परिवहन के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि गांव समिति में बैठक कर रेत निकाले जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पंचायत का इससे कोई लेना देना नहीं है।

आवास के आड़ में कालाबाजारी ?

ग्रामीणों के मध्य यह चर्चा भी जोरों पर है कि आवास निर्माण के नाम पर रेत निकाली जा रही है। लोगों का आरोप है कि जरूरत से अधिक मात्रा में रेत का उत्खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या आवास कार्य की आड़ में अवैध रेत कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को दुरुस्त करने दिया निर्देश

बेमेतरा। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई और कई कड़े निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई है। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि जिले में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दुर्घटना संभावित क्षेत्र का चिन्हांकन

कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉट का नए सिरे से सर्वे करें। जहाँ भी आवश्यक हो, तत्काल साइन बोर्ड, गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर), रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर लाइट लगाने के निर्देश दिए गए।

अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर ने सड़कों के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर हाईवे और मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने को कहा।

यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाए

कलेक्टर ने पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने वाले, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफसख्त चालानी कार्रवाई की जाए। विशेषकर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों के खिलाफ भी काउंसलिंग और कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

आवारा पशुओं पर नियंत्रण

राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख जिला मार्गों पर बैठने वाले आवारा मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए स्थानीय निकायों (नगर पालिका/पंचायत) को कांजी हाउस की व्यवस्था दुरुस्त करने और मवेशियों के गले में रेडियम बेल्ट लगाने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया।

जागरूकता अभियान

चलाया जाए कलेक्टर ने स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख चौक-चौराहों पर बैनर, पोस्टर और नुक्क ड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने कहा। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

झीरम घाटी के शहीदों को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगांव की श्रद्धांजलि सभा

डोंगरगांव नगर। कांग्रेस ने झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं की पुण्यतिथि शहादत दिवस बतौर मनाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगांव द्वारा ग्राम दिवानझिटिया में आहुत श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेसजनों ने दिवंगत नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेसजनों ने अपने नेताओं के लोकतंत्र के लिए त्याग व बलिदान को अक्षुण्य बनाए रखने संकल्प लिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनरतले आहुत श्रद्धांजलि सभा दौरान झीरम घाटी हमले में शहीद कांग्रेस नेताओं के त्याग, बलिदान तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि झीरम घाटी के शहीद नेताओं का बलिदान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कांग्रेस पार्टी सदैव उनके आदर्शों पर चलकर जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगांव के अध्यक्ष टिकेश साहू ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष टिकेश साहू, बलीराम साहू, रोशन यदु, अखिलेश नखत, मोहनीश साहू, लीलम गोस्वामी, नेतराम देशलहरे, प्रियंक जैन, शरद वैष्णव, कमल वैष्णव, रेवाराम साहू, संजय भट्टाचार्य, चुम्मन साहू, अशफाक शेरु तंवर, योगेश साहू, लीलेश पटेल, हेम सिंह साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

लक्ष्य फाउंडेशन के चौथी बैच में 20 से अधिक कैडेट्स अग्निवीर भर्ती में चयनित

बेमेतरा। लक्ष्य फाउंडेशन बेमेतरा द्वारा संचालित सेना भर्ती निशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण संस्था ने एक बार फिर शानदार सफलता हासिल की है। फाउंडेशन के चौथी बैच वर्ष 2025-26 के 20 से अधिक कैडेट्स का चयन भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में हुआ है। अग्निवीर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कुल 1163 जवानों का चयन हुआ। लक्ष्य फाउंडेशन बेमेतरा पिछले कई वर्षों से युवाओं को निशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण, रनिंग, अनुशासन एवं सेना भर्ती की तैयारी करवा रहा है। फाउंडेशन के प्रशिक्षकों की मेहनत और युवाओं के समर्पण का ही परिणाम है कि लगातार बड़ी संख्या में जवान सेना में चयनित हो रहे हैं। फाउंडेशन के संस्थापक मुख्य प्रशिक्षक पवन वर्मा व प्रशिक्षक रिटायर्ड सूबेदार हरीश अवस्थी तथा मार्गदर्शक लेफ्टिनेंट राहुल वर्मा, बेमेतरा निवासी डॉ गोकुल प्रसाद बंजारे अन्य सदस्यों ने चयनित सभी जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता पूरे बेमेतरा जिले के लिए गर्व की बात है। साथ ही जिन युवाओं का इस बार चयन नहीं हो पाया है, उन्हें निराश न होकर पुनः मेहनत और तैयारी जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया। साथ में नए चयनित सब इंस्पेक्टर राधिका यादव व शहर के रिटायर्ड फौजी सूर्या सिंह चौहान भी चयनित कैडेट को बहुत बहुत शुभकामना दिए।

108 संजीवनी एक्सप्रेस कर्मियों की सूझबूझ से एम्बुलेंस में हुआ सुरक्षित प्रसव

बेमेतरा। प्रदेश सरकार की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा 108 संजीवनी एक्सप्रेस एक बार फिर गर्भवती महिला के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की तत्परता, सूझबूझ एवं संवेदनशीलता से एक गर्भवती महिला का एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। वर्तमान में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम आनंदगांव निवासी मानसी, पति दीपक, उम्र 24 वर्ष को गर्भावस्था संबंधी जटिलता होने पर जिला चिकित्सालय बेमेतरा में भर्ती कराया गया था। महिला की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर रेफर किया। इसके बाद 108 संजीवनी एक्सप्रेस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के पायलट नीलमणि एवं ईएमटी कलावती

गायकवाड़ तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचे और गर्भवती महिला को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रायपुर के लिए रवाना हुए।

धरसीवां के पास बढ़ी प्रसव पीड़ा, एम्बुलेंस में ही कराया सुरक्षित प्रसव

रायपुर पहुंचने से पहले धरसीवां के आसपास महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईएमटी कलावती गायकवाड़ ने परिजनों की सहमति एवं पायलट नीलमणि के सहयोग से एम्बुलेंस में ही प्रसव कराने का निर्णय लिया। ईएमटी द्वारा सभी आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रियाओं एवं सावधानियों का पालन करते हुए सुरक्षित प्रसव कराया गया। कुछ ही देर में महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया।

मेकाहारा रायपुर में कराया गया भर्ती

सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा एवं नवजात शिशु को बेहतर देखभाल हेतु मेकाहारा रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। परिजनों ने विपरीत परिस्थितियों में तत्परता एवं मानवता का परिचय देते हुए सुरक्षित प्रसव कराने पर 108 संजीवनी एक्सप्रेस टीम, ईएमटी कलावती गायकवाड़ एवं पायलट नीलमणि का आभार व्यक्त किया।

बालोद नपा में 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात': तत्कालीन सीएमओ ने बांटा अवैध एक्सटेंशन

वर्तमान सीएमओ ने परिषद के सिर फोड़ा ठीकरा, 60 लाख के टेंडर में अफसरों की जंग शुरू

बालोद। नगर पालिका परिषद बालोद में प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन रायपुर को 14 महीने से बिना टेंडर 22त्न अधिक दर पर उपकृत करने के महा-घोटाले में अब अधिकारियों के बीच ही 'ब्लेम गेम' (आरोप-प्रत्यारोप) का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में घिरते नजर आ रहे वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी खिरोद्र भाई ने एक नया बयान देकर गेंद परिषद और तत्कालीन अधिकारी के पाले में डाल दी है, जिससे नगर पालिका के भीतर चल रही प्रशासनिक अराजकता पूरी तरह बेनकाब हो गई है। वर्तमान सीएमओ जिस एक्सटेंशन को परिषद का निर्णय बता रहे हैं, असल में नगर पालिका के खुद के रिकॉर्ड्स ने उनके इस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं।

45 दिन का समय था, फिर भी नहीं निकाला टेंडर

दस्तावेजों के अनुसार, निकाय चुनाव के लिए 17 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी हुई थी और 15 फरवरी 2025 को मतगणना के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो गई थी। एजेंसी का मूल अनुबंध 31 मार्च 2025 तक था। आचार संहिता हटने के बाद अधिकारियों के पास नया टेंडर करने के लिए पूरे 45 दिन का समय था। लेकिन नई चुनी गई परिषद को विश्वास में लिए बिना, तत्कालीन सीएमओ ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ठीक दो दिन पहले यानी 29 मार्च 2025 को एक विवादित आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के तहत एजेंसी को दिनांक 31.03.2026 तक या नई प्लेसमेंट एजेंसी से अनुबंध होने तक (जो भी पहले हो) के लिए ही पूर्व स्वीकृत 22 प्रतिशत अधिक की दर पर कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था।

आखिर नया टेंडर करने से क्यों बच रहे हैं जिम्मेदार?

आदेश की पहली शर्त ही यह थी कि नई प्लेसमेंट एजेंसी से अनुबंध होने तक। इसका साफ मतलब है कि नगर पालिका को तत्काल नया टेंडर जारी करना था। लेकिन अफसरों ने पूरे साल टेंडर प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाले रखा ताकि शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन को 22% अधिक की ऊंची दर का लाभ मिलता रहे। यह सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन और पद का दुरुपयोग है।

दिसंबर 2025 में परिषद ने कहा 'टेंडर करो', अफसर दबाकर बैठे रहे फाइल

प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, नगर पालिका की सर्वोच्च संस्था सामान्य सभा (परिषद) ने दिसंबर 2025 की बैठक में अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि आगामी वर्ष 2026-27 के लिए अनिवार्य रूप से नई निविदा आमंत्रित की जाए। नियमतः परिषद के इस आदेश के बाद जनवरी 2026 में ही टेंडर जारी हो जाना था। लेकिन अधिकारियों ने चहेती एजेंसी को बिना प्रतिस्पर्धा के मलाई खिलाने के लिए परिषद के इस सर्वोच्च आदेश को ही रददी की टोकरी में डाल दिया।

तत्कालीन साहब की मनमानी, वर्तमान साहब का 'कवर-अप' गेम

सच तो यह है कि यह अवैध एक्सटेंशन परिषद ने नहीं, बल्कि तत्कालीन सीएमओ ने मार्च 2025 में अपने एकल हस्ताक्षर से जारी किया था, जो छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों और वित्तीय संहिता का खुला उल्लंघन था। इसके बाद जब 31 मार्च 2026 को वह विवादित आदेश भी समाप्त हो गया, तो पिछले 50 दिनों से बिना किसी टेंडर के काम लिया जाता रहा। इस बीच माह मार्च 2026 का लगभग 10 लाख रुपये का भुगतान फंस गया। इस 'अवैध' भुगतान को निकालने के लिए मई 2026 को आनन-फानन में प्रेसीडेंट इन काउंसिल की अधिकार-विहीन बैठक (60 लाख के टेंडर पर पीआईसी को फैसले का अधिकार ही नहीं है) बुलाई और अब वर्तमान सीएमओ अपनी इस वित्तीय विफलता को छुपाने के लिए परिषद के नाम का झूठा सहारा ले रहे हैं।

धान उठाव और अंतिम निराकरण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : कलेक्टर गोपाल वर्मा

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने खरीफ विपणन वर्ष 2026 के तहत जिले में धान के उठाव एवं अंतिम निराकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और उपार्जन केंद्र प्रभारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धान उठाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर वर्मा ने प्रबंधकों एवं उपार्जन केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि भौतिक रूप से उपलब्ध धान का तीन दिनों के भीतर अंतिम निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपार्जन केंद्रवार समीक्षा करते हुए कहा कि उपलब्ध धान का जीरो शॉर्टेज के साथ उठाव कर लेखा मिलान कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन केंद्रों में धान की मात्रा अधिक है, वहां मिलर्स के साथ समन्वय स्थापित कर 29 मई के पहले संपूर्ण धान का उठाव किया जाए। साथ ही सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में हमाल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए ताकि उठाव कार्य प्रभावित न हो। कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिन केंद्रों में धान की शॉर्टेज अधिक पाई जाए।

संपादकीय

पेपर लीक मामलों में उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत

अगर खुद एनटीए की ओर से इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने वाला कोई शख्स ही प्रश्नपत्र लीक करने का आरोपी हो, तो ऐसे में किसी संस्था की साख की क्या अहमियत रह जाती है? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लाखों विद्यार्थी एक भरोसे के साथ जिस परीक्षा में अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बैठें, वह सिर्फ उनके हित में साबित हो, जिनकी पहुंच उसके प्रश्नपत्र तक हो।देश भर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी को सबसे अच्छे प्रबंधन के तहत संचालित करने का दावा किया जाता रहा है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इसमें जिस स्तर की गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसमें यह सवाल उठा है कि हर बार कार्रवाई के तौर पर कुछ औपचारिक और दिखावे के कदम उठा कर क्या परीक्षा के प्रश्नपत्र बाहर आने की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है?यह इस वर्ष फिर साबित हुआ है कि पहले की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया और ऐसे जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जिससे इस परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित हो। नतीजतन, इस महीने के शुरू में आयोजित नीट के प्रश्नपत्र लीक होने की खबर आई। फिर मामले के तूल पकड़ने के बाद परीक्षा को रद्द कर देना ही सबसे आखिरी उपाय माना गया, जिसकी वजह से करीब बाईस लाख विद्यार्थियों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया।सवाल है कि इस अफसोसनाक स्थिति के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए सबसे बेहतर व्यवस्था के तहत परीक्षाओं के आयोजन का भरोसा देती रही है, क्या नीट-यूजी में प्रश्नपत्र लीक होने सहित अन्य गड़बड़ियों की निरंतरता कायम रहने की स्थिति में अब भी वह अपनी साख और प्रतिष्ठा के बने रहने का दावा कर सकती है?प्रश्नपत्र लीक होने के तथ्य सामने आने, उसके राजस्थान के कई कोचिंग संस्थानों में पहुंचने और मोटी रकम लेकर विद्यार्थियों को बेचने की खबरों के बाद सरकार ने मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंपी। उसके बाद से अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एनटीए की एक विशेषज्ञ भी शामिल हैं।अगर खुद एनटीए की ओर से इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने वाला कोई शख्स ही प्रश्नपत्र लीक करने का आरोपी हो, तो ऐसे में किसी संस्था की साख की क्या अहमियत रह जाती है?गौरतलब है कि इस तरह की गड़बड़ियों पर काबू पाने के लिए राधाकृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट में एनटीए में ढांचागत सुधार की सिफारिश की थी। इसके अलावा, संसद में परीक्षाओं के संदर्भ में संगठित तौर पर पेपर लीक जैसी किसी गड़बड़ी के लिए दस वर्ष की कैद के प्रावधान वाला कानून पारित किया गया। साथ ही अन्य सभी कमियों को दुरुस्त करने के मद्देनजर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों सहित आधुनिक तकनीक से लैस बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई।इस सबके बावजूद अगर नीट-यूजी का प्रश्नपत्र लीक हो जाता है और यहां तक कि परीक्षा रद्द करने की नौबत आती है, तो यह किसकी नाकामी है? अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इस व्यापक गड़बड़ी का दायरा वैसे ही निचले स्तर के आरोपियों तक सिमटा हुआ है? ऐसा नहीं है कि नीट परीक्षा के आयोजन में यह कोई पहला मामला सामने आया है।

फिर कैसे मिले सुर मेरा–तुम्हारा

राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार सिरे से परवान चढ़ सकता है ? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बचती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ, लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय।

(उमेश चतुर्वेदी)

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं।

विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी हैं।

दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार सिरे से परवान चढ़ सकता है ? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बचती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय। लेकिन कांग्रेसी आलाकमान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। अपने पहले परिवार की पूरी स्वीकार्यता भले ही ना हो, लेकिन अगुआई कांग्रेस को ही चाहिए। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा रहे नीतीश कुमार ने निराशा में उसी मोदी का हाथ थाम लिया, जिनसे वे दूर हो चुके थे। इसके बाद का इतिहास सबको पता है।

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा

के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं। उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लॉक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। विपक्ष को उसी वक्त चेतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असर यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। बाकी कसर बीते विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है।

गौर करने की बात है कि जब भी सत्ता पक्ष के उफान में विपक्ष बह जाता है, उसकी एकता की छटपटाहट बढ़ जाती है। ज्यादातर यह अस्तित्व संकट टालने का यह फौरी उपाय होता है। तब वह हार के बाद वोटों के गुणा-गणित में जुट जाता है। फिर उसे इलहाम होता है कि अगर वह एक रहता तो वह भारी पड़ता। 1962 के आम चुनावों में नेहरू को फूलपुर की सीट पर सीधी चुनौती में हार मिलने के बाद लोहिया को भी कुछ ऐसा ही लगा। तब भारी उत्सुकता और उत्साह के बावजूद लोहिया हार गए थे। इसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। तब कांग्रेस को 44 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लोहिया को लगा कि विरोध में पड़े 56 प्रतिशत वोटों को अगर एक किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। गैर कांग्रेसवाद के बैनर के तले उन्होंने 1963 के उपचुनावों और 1967 के आम चुनावों में इसे आजमाया। इसका असर यह हुआ कि आठ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। तब से सत्ता में आने वाली पार्टी के खिलाफ बाकी विपक्ष की एकता के सुर उठने की परंपरा बन गई है। कभी यह कांग्रेस के खिलाफ होता था, जिसमें वाममोर्चा और जनसंघ- बीजेपी भी शामिल रहते थे, अब यह भाजपा के खिलाफ हो रहा है।

प. बगाल के बीते विधानसभा चुनाव में ममता को जहां करीब 42 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं बीजेपी को करीब 46 प्रतिशत। कांग्रेस को 2.97 और वाममोर्चे को 4.45 प्रतिशत वोट मिले हैं। गैर बीजेपी वोटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 49 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। चुनावी राजनीति में सात प्रतिशत का अंतर बड़ा होता है। अब विपक्षी खेमे को लग रहा है कि अगर वे एक होते तो बीजेपी को ऐसी जीत नहीं मिलती। वैसे चुनावी गणित सामान्य गणित की तरह नहीं होता। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी को पांच लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में वह पिछड़ गई थी। चुनावी मैदान में जब सिर्फ दो खेमे होते हैं, तब मतदाताओं के बीच लंबवत ध्रुवीकरण हो जाता है। तब बिखराव वाले आंकड़े भी बदल जाते हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ दिखा, जब बीजेपी सब पर भारी रही।

संसदीय चुनाव में सफलता के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की 99 सीटों के बाद 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी विपक्ष का दूसरा बड़ा दल है। तीसरे नंबर पर 29 सीटों के साथ ममता ही हैं। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक के पीछे ममता का भी विचार था, फिर भी ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस या ब्लॉक के दूसरे दलों को तवज्जो दिया। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस की खींचतान जारी रही। विपक्ष के किसी भी दल ने एकता की कीमत पर त्याग स्वीकार नहीं किया। विपक्षी खेमे का संकट यह है कि वह अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सहयोगियों से हिस्सेदारी बांटना ही नहीं चाहता।

मजबूत एकता के लिए विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य साफ छवि वाला चेहरा होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा चेहरा है भी नहीं। ममता बड़ी नेता तो हैं, लेकिन उनकी तुनकमिजाजी उन्हें सर्वमान्य चेहरा मानने के राह की बड़ी बाधा है। राहुल मोदी-शाह की जोड़ी को चाहे जिस अंदाज में चुनौती दें, मोदी विरोधी बौद्धिकों को उनका यह अंदाज चाहे जितना भी पसंद हो, लेकिन आमजन को उनमें कई बार बचकानापन नजर आता है तो कई मर्तबा प्रहसन। स्टालिन चाहे जितनी अच्छी तमिल बोलें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर स्वीकार्यता के लिए वे अयोग्य हैं। इसी तरह केजरीवाल के पास बड़ा आधार नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की तो, वे भी जमीनी राजनीति के बजाय बयानों के गुब्बारे उड़ाने के उस्ताद होते गए हैं।

आपसी अहं के टकराव के चलते नीतीश विपक्षी खेमा छोड़ चुके हैं। दूसरी बड़ी नेता ममता को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त मिल गई है। अखिलेश को भी अगले साल उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में बीजेपी से दो-दो हाथ करना है। बीजेपी की कोशिश उन्हें तीसरी बार शिकस्त देने की होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रही तो उसके सामने दूर-दूर तक कोई चुनौती नहीं होगी। ऐसे में विपक्षी खेमे का संकट बड़ा है। अतीत के विपक्षी व्यवहार से नहीं लगता कि शायद ही भविष्य में कोई मजबूत मोर्चा बन सके। खुलकर विपक्षी खेमा भले ही ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जरूर गुनगुना रहा है, कैसे मिले सुर हमारा-तुम्हारा....लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आवारा कुत्तों की भयावह समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- लेकिन जिम्मेदारी तय किए बिना कैसे बनेगी बात?

(संतोष कुमार पाठक)

लेकिन क्या इससे देश के आम नागरिकों को खुश होना चाहिए? क्या इससे देश में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों - खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिल पाएगी? यह इतना भी आसान नहीं है। जब तक किसी खास अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और दूसरी जगह भेजने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने के लिए दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत देश भर में कुत्ता काटने की घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में अपने पहले के आदेश की फिर से याद दिलाते हुए कहा कि सड़क के कुत्तों पर 7 नवंबर, 2025 को दिया गया उनका आदेश ही लागू होगा। इन आदेशों को लागू करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए और जो अधिकारी इनका पालन न करे, उन पर विभागीय और अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।

लेकिन क्या इससे देश के आम नागरिकों को खुश होना चाहिए? क्या इससे देश में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों - खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिल पाएगी? यह इतना भी आसान नहीं है। जब तक किसी खास अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद व्यवहारिक स्थिति तो यही है कि ज्यादातर राज्य सरकारें और जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लेती नज़र नहीं आ रही है। इसलिए इस आदेश को लागू करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी यानी सीधे ष्ठरूको ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए गए आदेश के 6 महीने बीत जाने के बावजूद हालत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का नगर निगम - एमसीडी कुत्तों को रखने के लिए एक डॉग सेंटर तक तैयार नहीं कर पाई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जो कुत्ता एक से अधिक बार लोगों को काट चुका हो, उसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद समेत राज्य के कई जिलों में भी अभी भी जरूरी डॉग सेंटर का निर्माण फाइल्स में ही अटका पड़ा है। क्या इस तरह की लापरवाही और लेट-लतीफी के लिए जिलों के डीएम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए?

समय आ गया है कि हर जिले, हर राज्य और सबसे ऊपर सीधे सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए जिस पर कॉल करने वाले हर व्यक्ति को तुरंत उनकी शिकायत का एक नंबर भी अलॉट कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो टोल फ्री नंबर पर बैठने वाले अदालत के स्टॉफ का खर्चा भी लोगों से ले सकता है और इसके लिए प्रति कॉल 3 से 5 रुपए की राशि भी फिक्स की जा सकती है लेकिन हर कॉल का उचित फॉलोअप सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस काम को युद्धस्तर पर करने की जरूरत है क्योंकि भारत में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। वैसे तो देश में कुत्तों द्वारा काटने के सारे आंकड़े दर्ज नहीं करवाए जाते हैं लेकिन जो भी आंकड़े दर्ज होते हैं, उसके मुताबिक वर्ष 2024 में हर मिनट पर डॉग बाइट के 7, हर घंटे में 430, रोजाना 10,321 , हर महीने 3,09,643 और वर्ष भर में 37,15,713 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी सरकार भी यह मान रही है कि एक साल में 37 लाख से भी ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार बनते हैं। वहीं वर्ष 2025 में कुत्तों के काटने की संख्या 47 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है।

सरकारी रिपोर्ट की माने तो, भारत में हर साल रेबीज के कारण 300 लोगों की मौत होती है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में हर साल रेबीज के कारण 18 से 20 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। यहां इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस तरह के ज्यादातर मामले आंकड़ों में दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2019 में हुई पशु जनगणना में, देश में आवारा कुत्तों की संख्या 1.53 करोड़ बताई गई थी। लेकिन एक मोटे अनुमान के तौर पर यह माना जाता है कि देश में वर्तमान में आवारा कुत्तों की संख्या 6 से 7 करोड़ के लगभग हो गई है।

यह समस्या हर गुजरते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। मोहल्लों, कॉलोनियों, सोसायटियों यहां तक कि पार्कों में भी इन आवारा कुत्तों ने कब्जा जमा रखा है। लगभग हर मोहल्ले/कॉलोनी और सोसायटी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन्हें अपने घर ले जाकर खाना नहीं खिलाएंगे, बल्कि उनकी जिद होगी कि वो इन्हें बाहर ही खाना खिलाएंगे। रही-सही कसर देश के टीवी चैनलों पर आने वाले तथाकथित ज्योतिषियों ने पूरी कर दी है, जो खास रंग के कुत्तों को खाना खिलाने पर किस्मत बदल जाने यानी अच्छे दिन आने का सपना दिखाकर इस समस्या को और ज्यादा भयावह बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

पीएम की यात्रा से पूरी दुनिया में मची हलचल, भारत की ताकत देखकर दंग रह गए यूरोपीय देश

(नीरज कुमार दुबे)

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत और नॉर्वे की साझेदारी अब स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास, हरित नौवहन और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के भविष्य के लिए निर्णायक कदम बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नॉर्वे यात्रा ने भारत और नॉर्वे के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ओस्लो में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने की घोषणा की। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, समुद्री अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, निवेश और व्यापार के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग का आधार भी माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस नई साझेदारी से जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री अर्थव्यवस्था और टिकाऊ विकास के क्षेत्रों में सहयोग को रणनीतिक दिशा मिलेगी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को उन ताकतों के खिलाफ साथ खड़ा होना होगा जो कूटनीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी का हथियार की तरह उपयोग करती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत और नॉर्वे की साझेदारी अब स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास, हरित नौवहन और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के भविष्य के लिए निर्णायक कदम बताया।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि चार दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया है। ऐसे समय में जब भारत पारंपरिक साझेदारों पर निर्भरता कम कर नए आर्थिक सहयोगियों की तलाश कर रहा है, नॉर्वे एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है। नॉर्वे का सरकारी पेंशन कोष दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु

निवेश कोषों में गिना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में उसने भारतीय बाजारों में निवेश लगातार बढ़ाया है।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के मामले में नॉर्वे का हिस्सा 1.95 प्रतिशत था, जो 2025 तक बढ़कर 3.87 प्रतिशत हो गया। महामारी के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी तेजी आई है। भारत को हाल के वर्षों में नॉर्वे से लगभग 693 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। व्यापार के स्तर पर भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत का नॉर्वे को निर्यात बढ़कर लगभग 472 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात लगभग 635 मिलियन डॉलर रहा।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को नया आयाम देना भी शामिल है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने नॉर्वे में पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा, कार्बन नियंत्रण, जैव आधारित प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। मोदी को यह सम्मान भारत-नॉर्वे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री को मिला 32वां विदेशी सम्मान है।

इसके अलावा, भारत और नॉर्वे के अनुसंधान संस्थानों के बीच संयुक्त कार्यशालाओं, अनुसंधान परियोजनाओं और वैज्ञानिक आदान प्रदान की भी योजना बनाई गई है। विशेष रूप से समुद्री ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा पर सहयोग भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करेगा और कार्बन तटस्थता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त सतत विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था, समुद्री विज्ञान, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है।

प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ बैठकें भी इस दौरे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहीं। उन्होंने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रन फ्रॉस्टडॉटिर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ अलग अलग वार्ता की। इन बैठकों में व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

हम आपको बता दें कि नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। इन पांच देशों की संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद क्षमता 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा सतत समुद्री शासन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व रखते हैं। साथ ही ओस्लो में आयोजित तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत और इन देशों के बीच प्रौद्योगिकी, हरित परिवर्तन, रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था और आर्कटिक सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा तेज हुई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच निवेश समझौते को सहयोग की अधूरी कड़ी बताया। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हाल में हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से भारत में एक लाख करोड़ डॉलर तक का निवेश आ सकता है और अगले पंद्रह वर्षों में दस लाख रोजगार सृजित हो सकते हैं।

हम आपको बता दें कि फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के साथ भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। फिनलैंड की सौ से अधिक कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, जबकि डेनमार्क की कई कंपनियों ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत नए कारखाने स्थापित किए हैं। आइसलैंड में भारतीय संस्कृति, योग, संगीत और भारतीय भोजन के प्रति विशेष रुचि देखी जा रही है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे और नॉर्डिक देशों की यह यात्रा केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हरित विकास, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं का संकेत मानी जा रही है। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ती निकटता आने वाले वर्षों में वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी के नए मॉडल के रूप में उभर सकती है।

संक्षिप्त समाचार

मोबाइल पर बात करते हाईवा चालक पर पुलिस का शिकंजा

रायपुर। मोबाइल पर बात करते हुए तेज रफ्तार हाईवा सड़क पर दौड़ रहा था, रेत से ओवरलोड यह भारी वाहन किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा था, लेकिन धमतरी पुलिस की सतर्क नजर ने बीच रास्ते ही चालक का खेल खत्म कर दिया। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में कोलियारी मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने हाईवा क्रमांक छत्र 07 छ 9995 अशोक लेलैंड 10 चक्का को रोका, जहां चालक शाहिल वर्मा पिता चन्द्रशेखर वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पाहंदा थाना रानीतराई जिला दुर्ग मोबाइल फोन पर बात करते हुए खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़ा गया। जांच में खुलासा हुआ कि वाहन में तय क्षमता से 3 टन 830 किलोग्राम अधिक रेत भरी गई थी। इतना ही नहीं चालक जरूरी दस्तावेज भी मौके पर पेश नहीं कर सका और वाहन के पीछे नंबर तक अंकित नहीं मिला। पुलिस ने इसे सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तत्काल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196, 50(2)/177, 184, 21(25)/177, 3/181 एवं 113/194(1) के तहत कार्रवाई की और इस्तगासा तैयार कर आरोपी चालक को माननीय न्यायालय में पेश किया। एसपी धमतरी के निर्देश पर जिलेभर में लगातार चल रहे यातायात अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों, ओवरलोड वाहनों और लापरवाह ड्राइवरों पर सख्त नजर रखी जा रही है।

भखारा में शराब माफिया पर पुलिस का धावा, 30 पौवा देशी शराब संग आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रोशन राइस मिल के पास नीम पेड़ पुल के नीचे चल रहा अवैध शराब का धंधा उस वक्त बेनकाब हो गया, जब भखारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। धमतरी जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफलगातार चल रहे अभियान के बीच थाना भखारा पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खुलेआम देशी शराब बेचकर माहौल बिगाड़ रहा है, जिसके बाद टीम ने तत्काल घेराबंदी की और मौके से राजु साहू उर्फ तुलसी साहू पिता महेत्तर साहू उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 03 भखारा थाना भखारा जिला धमतरी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी प्लेन शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 2400 रुपए आंकी गई। पुलिस ने मौके पर ही शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफथाना भखारा में अपराध क्रमांक 54/26 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिलेभर में मादक पदार्थ, जुआ-सट्टा और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

तीसरी बार जला ट्रांसफार्मर भीषण गर्मी में ग्रामीण परेशान

रायपुर। ग्राम नेवसा में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बस्ती क्षेत्र में लगा ट्रांसफार्मर पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर तीसरी बार जल गया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार बिजली गुल रहने से लोगों को भीषण गर्मी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती में लगाए गए ट्रांसफार्मर की क्षमता बेहद कम है, जबकि बिजली का लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस मामले को लेकर समाज सेवी, एसईसीएल यूनियन नेता अजय राठौर ने बिजली विभाग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नेवसा के लोग लंबे समय से बिजली संकट झेल रहे हैं और विभाग की लापरवाही के कारण आम जनता परेशान हो रही है। अजय राठौर ने बिजली विभाग से मांग करते हुए कहा कि गांव में तत्काल अधिक क्षमता वाला नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बार-बार ट्रांसफार्मर जलने की समस्या खत्म हो सके और भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं, गांव के लोगों ने भी जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

वरिष्ठ नागरिकों से आटो चालक कर रहे दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन ध्यान दें

रायपुर। शहर में इन दिनों ऑटो चालकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से आए दिन दुर्व्यवार किये जाने की घटना देखने में आ रही है। शादी विवाह का मौसम होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही राजधानी में विभिन्न स्थलों पर हो रही है। उदर ऑटो एवं ओला चालकों द्वारा भी गंतव्य स्थल जाने के लिए किराया वसूल करने में लोकेशन के नाम पर सौ दो सौ रुपये अधिक वसूले जा रहे है। इधर रेलवे स्टेशन एवं एयर पोर्ट में आने जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों से गंतव्य स्थल बताने के बावजूद भी बीच रास्ते में ऑटो चालकों द्वारा और कितना दूर है पूछ पूछकर परेशान किया जा रहा है। वहीं प्राइवेट ऑटो करने पर भी कुछ गुंडा किस्म के ऑटो चालकों द्वारा चिल्हर सवारी लेकर भी लोगों को तंग किया जा रहा है।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे

पर्यटन के जरिए नई पहचान गढ़ेगा छत्तीसगढ़-मुख्यमंत्री साय

- छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने लाना हमारा उद्देश्य : मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को मिल रही नई गति

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी नई पहचान गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने, निवेश अनुकूल नीतियों और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण प्रदेश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अपने निवास कार्यालय में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में देश की प्रतिष्ठित इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक नैसर्गिक विरासत की अमूल्य धरा है, जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं

तेजी से बढ़ी हैं और पर्यटकों के लिए बेहतर ठहराव, परिवहन तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में लगातार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और इसी क्रम में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई गई है, जो प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निवेश से पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। बैठक के दौरान इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के समक्ष अपने निवेश प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए और बताया कि कंपनी छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगभग 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की योजना पर कार्य कर रही है, जिसे शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस निवेश से प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है तथा सभी आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश के रास्ते व्यापक रूप से खुले हैं। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक अधोसंरचना, उच्चस्तरीय सुविधाओं और निवेश प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से विकसित करने की दिशा में विशेष पहल कर रही है। प्रदेश की बेहतर मानसूनी परिस्थितियां, समृद्ध प्राकृतिक संपदा और निवेश अनुकूल नीति पर्यटन विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही हैं।

नौतपा में बदलेगा मौसम का मिजाज बारिश के आसार, आंधी का अलर्ट....

रायपुर। ब्रज योग में चंद्रप्रधान रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव के प्रवेश के साथ ही नौतपा की शुरूआत कल से हो गई है, इस बार नौतपा में मौसम के तीन रंग देखने को मिलेंगे। शुरुआत के तीन दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके बाद हल्की राहत मिलेगी, फिर 29 और 30 मई से बारिश व बूंदाबांदी का दौर शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर इस बार नौतपा से पहले गर्मी ने हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है, इसलिए लोगों को नवतपा में राहत मिलने की उम्मीद है। नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने शहरवासियों को झुलसा दिया है। मई के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई भीषण गर्मी मई के अंतिम सप्ताह तक जारी है। इस साल की तेज गर्मी ने लोगों को खासा परेशान किया है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। वहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि बीच-बीच में कुछ सिस्टम सक्रिय होने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन वह नाकाफी रही। इस बार आए तूफान भी गर्मी से राहत नहीं दिला सके। वर्तमान में उत्तर-पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार सीजन के उच्च स्तर पर बना हुआ है। रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार, नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है। इस बार नौतपा ज्यादा नहीं तपेगा। शुरुआती तीन दिनों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ेगा। इसके बाद 27 मई की शाम से तापमान में गिरावट शुरू होगी, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। फिर 29 और 30 मई से बूंदाबांदी व बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। अंतिम चार दिनों में बदली छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन शुरुआती बारिश के कारण उमस लोगों को परेशान कर सकती है। एचपी चंद्रा का कहना है कि नवतपा के शुरुआती तीन दिनों में तेज गर्मी पड़ेगी। इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। आगे चलकर बादल, बारिश और आंधी की स्थिति बनेगी।

जलते दीये से भड़की भीषण आग, घर का पूरा सामान हुआ राख

रायपुर। जिले के सिविल लाइन थाना पुलिस क्षेत्र के 27 खोली इलाके में एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार घर में रखे जलते दीये से आग लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक घर में रखा फर्नीचर, कपड़े, घरेलू सामान और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग तेजी से फैल रही थी।

खाद संकट पर भी घिरी सरकार

बैज के बयान पर गरमाई सियासत कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने हुए

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बैज के बयान का समर्थन किया है, वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे कांग्रेस की निम्नस्तरीय राजनीति और मानसिकता का परिचायक बताया है। अमरजीत भगत ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन यात्राओं से देश

को क्या उपलब्धियां मिली हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केवल औपचारिक मुलाकातों और तस्वीरों तक सीमित रहने से देशहित के परिणाम नहीं मिलते। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी लगातार मर्यादा और शिष्टाचार की सीमाएं लांघ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा राजनीतिक संवाद के स्तर को गिराने वाली है। साव ने दावा किया कि इसी प्रकार की बयानबाजी के कारण कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है। प्रदेश सरकार के 'सुशासन तिहार' अभियान को लेकर भी दोनों दलों के नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रशासनिक सख्ती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार शुरुआत से ही प्रभावी निगरानी रखती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने प्रदेश में भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

हसदेव प्लांट की दो यूनिट ठप.बिजली संकट गहराया

रायपुर। संवाददाता

प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण घरों, दफ्तरों और उद्योगों में एसी, कूलर और पंखों का उपयोग चरम पर है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की मांग 6000 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस भारी मांग के बीच छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के सबसे बड़े संयंत्र हसदेव थर्मल पावर स्टेशन की दो इकाइयों के बंद होने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भारी दबाव आ गया है। कोरबा स्थित हसदेव थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। यहां 210-210 मेगावाट की चार और 500 मेगावाट की एक विस्तार इकाई स्थापित है। अप्रैल महीने में झाबू राखड़ बांध के क्षतिग्रस्त होने के बाद से सुरक्षा और मरम्मत के मद्देनजर 210-210 मेगावाट की दो इकाइयों को बंद रखा गया है। इसके कारण वर्तमान में 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन पूरी तरह ठप है। फिलहाल चालू तीन इकाइयों से केवल 745 मेगावाट के आसपास ही उत्पादन हो पा रहा है, जो इस भीषण गर्मी में मांग के लिहाज से काफी कम है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सेंट्रल सेक्टर (केंद्रीय कोटे) से प्रतिदिन लगभग 3700 मेगावाट बिजली ड्रा (खर्च) करनी पड़ रही है। इसके अलावा डीएसपीएम पावर प्लांट में 500 मेगावाट क्षमता वाले इस संयंत्र से करीब 430 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। मड़वा प्लांट में 1000 मेगावाट की क्षमता वाले इस संयंत्र से लगभग 932 मेगावाट बिजली बन रही है। इन तमाम प्रयासों और केंद्रीय कोटे पर निर्भरता के बावजूद प्रदेश में पीक ऑवर्स के दौरान लगभग 150 मेगावाट बिजली की कमी बनी हुई है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि एनटीपीसी ने भी राज्य को होने वाली आपूर्ति में पहले की तुलना में कटौती की है। उत्पादन में कमी और ओवरलोडिंग का असर अब राज्य के कई इलाकों में दिखाई देने लगा है, जहां लगातार लो-वोल्टेज और पावर ट्रिपिंग (बिजली गुल होना) की शिकायतें आ रही हैं। इसके साथ ही, एचटीपीएस की दो इकाइयों के बंद रहने से बिजली कंपनी को प्रति घंटे दो करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मोवा अंडरब्रिज बंद होने से ओव्हरब्रिज में जाम से आवाजाही प्रभावित...

रायपुर। लगभग दो माह तक अंडरब्रिज बंद रखने के उपरांत मई माह में खुले ओव्हरब्रिज में पुनः सीपेज की समस्या होने पर इन दिनों अंडरब्रिज पुनः सुधार कार्य के नाम पर बंद कर दिया गया है। मोवा ओव्हरब्रिज में सवेरे 9 बजे से लेकर दिन के एक बजे तक यातायात जाम होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं शाम को पुनः पांच बजे से लेकर रात 9 बजे तक यातायात जाम होने से लौटने वाले नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञातव्य है कि मोवा ओव्हरब्रिज से लगभग दो दर्जन से अधिक कालोनियां बनी हुई है जिनका विस्तार मोवा चौक से लेकर पुरानी विस सड्डू मार्ग विभिन्न अपार्टमेंट्स में है यहां से लगभग सुबह शाम 25 से 30 हजार की आबादी 24 घंटों में आवाजाही करती है। संबंधित जोन कमिश्नरों यातायात पुलिस के अधिकारियों एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नागरिकों द्वारा यातायात सुगम के लिए आवाजाही के संबंध में अनेकोंबार मौखिक एवं लिखित तौर पर अवगत कराया गया है इसके बाद भी समस्या जस की तस है। जेठ की चिलचिलाती धूप में जहां शहर का तापमान 44 45 डिसी दर्ज किया जा रहा है वहां एक एक घंटे यातायात के नाम पर जाम होने पर दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है

शिक्षा, संगठन और संस्कार से ही समाज की प्रगति संभव: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी

- जांजगीर-चांपा के कापन और बलौदा में सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए वित्त मंत्री
- अघरिया और स्वर्णकार समाज के सामुदायिक भवनों का लोकार्पण

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं जांजगीर-चांपा जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी आज जांजगीर-चाम्पा जिले के कापन और नगर पंचायत बलौदा में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कापन में अखिल भारतीय अघरिया समाज के क्षेत्रीय सभा सह सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। वहीं, बलौदा के जंगलवा डबरी में स्वर्णकार समाज के 'स्वर्ण मंडपम' सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कापन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा, संस्कार और अवसर उपलब्ध कराकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकजुटता, सकारात्मक सोच और सामुदायिक भावना को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह ने कहा कि अघरिया समाज शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकजुटता में ही निहित होती है। वहीं, पूर्व संसदीय सचिव श्री अंबेश जांगड़े ने कहा कि यह नवनिर्मित भवन सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा। नगर पंचायत बलौदा में आयोजित स्वर्ण मंडपम सामुदायिक भवन के लोकार्पण समारोह में वित्त मंत्री ने स्वर्णकार समाज द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज के पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

हितग्राहियों विभिन्न योजनाओं से किया गया लाभान्वित

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना शासन की पहली प्राथमिकता -उपमुख्यमंत्री.....

- उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री शर्मा भनसुला में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में हुए शामिल

रायपुर/ संवाददाता

सुशासन तिहार 2026 के तहत आज मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी के ग्राम पंचायत भनसुला में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री द्वारा जिले की महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का मोहला ब्रांड के रूप में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य शासन और प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और सरलता के साथ पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और किसी भी समस्या या आवश्यकता को प्रशासन तक सीधे पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं एवं हर वर्ग के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो तथा जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि आज राज्य नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभाग संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखें। ग्राम पंचायत भनसुला क्लस्टर के 15 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शिविर में शामिल हुए।

संक्षिप्त समाचार

नवविवाहिता ने लगाई फांसी, घर में फंछे पर लटका मिला शव

रायपुर। जिले में एक नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का शव उसके घर में फांसी के फंद्दे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह मामला मानिकपुर चैकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान प्रीति उर्फ बेबी (26) के रूप में हुई है, जो कृष्णा नगर बस्ती में रहती थी। बताया जा रहा है कि महिला का शव घर में लोहे के एंगल पर चुन्नी के सहारे फंद्दे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतका का एक तीन साल का बेटा भी है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है।

भाजपा विधायक भी नहीं बच पाए साइबर ठगी से

रायपुर। रायपुर में साइबर ठगों ने इस बार भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा को अपना निशाना बनाया। आरोपी ने खुद को भाजपा के वरिष्ठ नेता का निजी सहायक (पीए) बताकर भरोसा जीता और डीजल भरवाने के नाम पर पैसों की मांग कर दी। भरोसे में आकर विधायक की ओर से 10 हजार रुपए ट्रांसफर करा दिए गए, लेकिन बाद में पूरा मामला ठगी निकला। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने फोन कर खुद को भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता नितिन नवीन का पीए बताया। उसने कहा कि वह भुवनेश्वर जा रहा है और रास्ते में ड्राइवर से विवाद होने के कारण परेशानी में फंस गया है। आरोपी ने तत्काल पैसों की जरूरत बताते हुए पहले 4500 रुपए मांगे। मानवीय आधार पर मदद करने की नीयत से विधायक पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर के सेवक नारायण मिश्रा के जरिए आरोपी के खाते में कुल 10 हजार रुपए ट्रांसफर करवा दिए। लेकिन करीब डेढ़ घंटे बाद जब आरोपी ने फिर से पैसों की मांग की, तब विधायक को शक हुआ। शक होने पर विधायक ने सीधे नितिन नवीन के कार्यालय में संपर्क किया। वहां से पता चला कि उस नाम का कोई भी व्यक्ति कार्यालय में कार्यरत नहीं है। इसके बाद तुरंत खम्हारडीह थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस अब मोबाइल नंबर और बैंक खाते के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आंख बंद कर भरोसा न करें। पैसे भेजने से पहले संबंधित व्यक्ति की पूरी तरह पुष्टि जरूर करें।

डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

रायपुर। जिले के देवभोग स्थित देवमाता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 130-ष्ट पर शव रखकर चक्काजाम किया और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका का नाम भानुमति मांझी (30 वर्ष) बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण प्रसूता की मौत हो गई।

वार्डो को मिली 04 करोड़ 85 लाख रू. के विकास कार्यो की सौगात

छत्तीसगढ़ राज्य नई ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा

- उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर श्रीमती राजपूत ने किया 03 करोड़ 75 लाख रू. के विकास कार्यो का भूमिपूजन एवं 01 करोड़ 10 लाख रू. के कार्य का किया लोकार्पण

रायपुर/ संवाददाता

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में लगातार जारी विकास कार्यों की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज निगम के विभिन्न वार्डो को 04 करोड़ 85 लाख रूपये के विकास कार्यो की सौगात प्राप्त हुई। प्रदेश के वाणिज्य उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, आबकारी व श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 03 करोड़ 75 लाख रूपये के विकास कार्यो का भूमिपूजन किया गया, वहीं 01 करोड़ 10 लाख रूपये के विकास कार्य का लोकार्पण भी सम्पन्न हुआ। इस मौके पर सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, पार्षद नरेन्द्र देवांगन, अशोक चावलानी सहित निगम के अन्य पार्षदगण व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्र. 04 राताखार पुल से बजरंग चैक होते हुये बाईपास सड़क तक 02 करोड़ रूपये की लागत से सी.सी.सड़क का निर्माण कार्य किया जाना हैं, इसी प्रकार वार्ड क्र. 04 राताखार सतनाम भवन परिसर के पास 15 लाख रूपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष व किचन शेड का निर्माण, वार्ड क्र. 03 राताखार मुक्तिधाम में 45 लाख रूपये की लागत से व्हूम वेस्ट प्रदूषण मुक्त

दाहगृह का प्रदाय स्थापना संचालन एवं संधारण कार्य कराया जाना हैं। इसी प्रकार वार्ड क्र. 18 कोहड़िया स्थित ब्रम्हकुमारी प्रजापति आश्रम के पास 10 लाख रूपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण, वार्ड क्र. 17 भैंसखटाल ढोढ़ीपारा में नहर किनारे सूरज बरेठ घर के पास 06 लाख रूपये की लागत से सांस्कृतिक मंच एवं अन्य विस्तार कार्य तथा वार्ड क्र. 03 अंतर्गत 99 लाख 78 हजार रूपये की लागत से टी.पी.नगर जोन कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया जाना हैं, इन सभी विकास कार्यो का भूमिपूजन आज उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान किया गया, वहीं 01 करोड़ 09 लाख 51 हजार रूपये की लागत से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सेंट्रल स्टोर से स्टेडियम चैक तक रेलिंग सहित डिवाईडर एवं विद्युतीकरण कार्य निगम द्वारा कराया गया है, जिसका लोकार्पण आज उनके करकमलों से किया गया। इस अवसर पर दिये गये अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्राप्त हो रहे लगातार मार्गदर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास कर रही है। उन्होने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने हम सबको छत्तीसगढ़ राज्य को तोहफा दिया था, और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमारे छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का कार्य कर रहे हैं। उन्होने कहा कि 15 वर्षो तक डॉ.रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन्होने जब छत्तीसगढ़ की कमान संभाली उस समय प्रदेश की स्थिति ठीक नही थी, किन्तु उन्होने छत्तीसगढ़ राज्य का तेजी से विकास किया तथा छत्तीसगढ़ के विकास पुरूष कहलायें। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि विगत कुछ वर्षो से प्रदेश का विकास थम गया था किन्तु पिछले 02 वर्षो से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में विकास को पुनः गति व दिशा दी हैं तथा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नई ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक ओर जहाँ प्रदेश में उद्योग, धंधे बढ़ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, अधोसंरचना विकास के कार्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केन्द्र व राज्य सरकार की दर्जनों जनकल्याणकारी व गरीब हितैषी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर गरीब, निर्धन परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डो में व्यापक स्तर पर विकास कार्य संपादित हो रहे हैं

महापौर ने विकास कार्यो का किया भूमिपूजन......

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के नेताजी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड कमांक 15 गुढियारी महावीर स्कूल के पीछे क्षेत्र में पहुंचकर रायपुर पश्चिम विधायक एवं प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री राजेश मूणत और नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने अधोसंरचना मद अंतर्गत 38 लाख रू. की स्वीकृत लागत से वार्ड 15 में नील के घर से राव के घर तक रोड निर्माण कार्य, शुभम चंद्राकर के घर के पास गली में रोड निर्माण कार्य, अन्ना चौक से शिव मंदिर लाईन में नाली निर्माण कार्य, मानस भवन गुढियारी के पीछे नाली निर्माण कार्य, डीडी नगर के आस पास के क्षेत्र एवं हेमा निवास के सामने साहू जी के घर तक एवं ब्रम्हानंद किराना स्टोर्स के पीछे गली में वर्मा जी के घर तक नाली चौड़ीकरण मरम्मत एवं नाली व पुलिया निर्माण कार्य शीघ्र करवाने नगर निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल नगर निगम खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग अध्यक्ष नंदकिशोर साहू, जोन 1 जोन अध्यक्ष गज्जू साहू, नेताजी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड पार्षद राजेश देवांगन, पूर्व पार्षद ओंकार बैस, विनोद अग्रवाल, जोन 1 जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर, कार्यपालन अभियंता द्रोणी कुमार पैकरा, सहायक अभियंता शरद देशमुख, उपअभियंता गोपाल प्रधान सहित बडी संख्या में वार्ड 15 क्षेत्र के निवासी गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिको, नवयुवको बच्चों, आमजनों की उपस्थिति में श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर भूमिपूजन करते हुए कार्यारंभ कर नागरिको को शानदार सौगात दी ।

बस्तर विकास के लिए तैयार...कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में-देवलाल ठाकुर

रायपुर/ संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक निर्धारित समय सीमा तय कर बस्तर को एक विकसित क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है। जिसके लिए बस्तर पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। नक्सलियों की मददगार कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं चाहा कि बस्तर का विकास हो और बस्तर में विकास की धारा प्रवाहित हो। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने नक्सलियों का समर्थन भी किया है जो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी नक्सलियों के साथ है आदिवासियों के साथ नहीं।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने एक बार फिर बस्तर

का दौरा करके बस्तर में नक्सलियों की समाप्ति के बाद बस्तर को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। आने वाले 5 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करेगी। एक निर्धारित समय सीमा तय कर आदिवासियों के विकास के लिए, बस्तर के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सहकारिता के क्षेत्र में आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए, बस्तर क्षेत्र के लोगों को विकास से जोड़ने के लिए, बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, जिस प्रकार से देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी कार्य कर रहे हैं जो बेहद ही सराहनीय है। ऐसे समय में विपक्षी दलों को भी साथ आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज आर्थिक रूप संपन्न हो। वहां पर लोगों को रोजगार मिले। इसी कारण से कांग्रेस के लोग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी का विरोध भी करते रहे।

गांव-गांव तक पहुँच रहा माहवारी स्वच्छता का संदेश

रायपुर/ संवाददाता

चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो 28 मई माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बीजापुर द्वारा चलाए जा रहे रेड डॉट अभियान ने पूरे जिले में जन-आंदोलन का रूप ले लिया है। गाँव की चौपाल से लेकर गारमेंट फैक्ट्री तक, हर जगह माहवारी को लेकर व्याप्त शर्म और मिथकों को तोड़ने का काम जोरों पर है। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अभियान का मुख्य केंद्र बनाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा किशोरी बालिकाओं व महिलाओं के साथ माहवारी स्वच्छता प्रबंधन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में सेनेटरी पैड के सही उपयोग, साफ-सफाई और पुरानी मान्यताओं पर खुलकर चर्चा हो रही है। बीजादूतीर स्वयंसेवकों की टोलियां गाँव-गाँव जाकर किशोरियों और महिलाओं से सीधा संवाद कर रही हैं। वहीं मितानिन दीदियां घर-घर जाकर महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता और रेड डॉट अभियान के महत्व से जोड़ रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिनों ने हथेली पर लाल बिंदी लगाकर माहवारी शर्म नहीं, सम्मान है का संदेश दिया। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बीजापुर के जिला रेड क्रॉस अधिकारी नरवेद सिंह ने भी रेड डॉट अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई। रेड क्रॉस के सदस्यों ने किशोरियों के बीच जाकर माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता सत्र लिए और हाइजीन किट वितरण में सहयोग किया। रेड क्रॉस के सदस्यों ने भी हथेली पर रेड डॉट लगाकर स्वास्थ्य ही सेवा है के संकल्प को दोहराया। जिले में चल रहे सुशासन शिविरो को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। शिविरों में आने वाले ग्रामीणों, विशेषकर पुरुषों को भी माहवारी स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। अधिकारियों-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से हथेली पर रेड डॉट लगाकर ष्चुप्पी नहीं, अब बात होगीष् का संकल्प लिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए बीजापुर की गारमेंट फैक्ट्री में कार्यरत सैकड़ों महिला श्रमिकों को महिला बाल विकास व जिला रेड क्रॉस सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान मे माहवारी स्वच्छता किट का वितरण किया गया। किट में सेनेटरी पैड, साबुन शामिल थी। महिला एवं बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि रेड डॉट सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि सोच बदलने का प्रतीक है। जिले में आंगनबाड़ी, मितानिन, बीजादूतीर, रेड क्रॉस और सुशासन तिहार जैसे सभी माध्यमों से हम ये संदेश घर-घर पहुँचा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी किशोरी माहवारी के कारण स्कूल न छोड़े और हर महिला को सम्मान मिले।

सुशासन तिहार में मन्नू को मिला वन अधिकार पत्र पुस्तिका,जताई खुशी...

रायपुर/ संवाददाता

राज्य में 'सुशासन तिहार' आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम खलीबा के रहने वाले श्री मन्नू को सुशासन तिहार के दौरान वन अधिकार पत्र पुस्तिका (पट्टा) प्राप्त हुआ है। अधिकार पत्र मिलने के बाद अन्नू ने खुशी जाहिर करते हुए शासन

एवं प्रशासन के प्रति आभार जताया है। श्री मन्नू ने बताया कि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वन अधिकार का वैध अधिकार नहीं होने के कारण कई शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आती थी। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान उन्होंने अपनी समस्या को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें भूमि का वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया। मन्नू ने कहा कि अब उनके नाम पर पट्टा होने से भविष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार से हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब हमें शासन की योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में सुशासन तिहार के माध्यम से जिले में आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

निगम ने गंदगी पाये जाने पर किचन को सीलबंद किया....

रायपुर। टीम प्रहरी अभियान अतर्गत रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही एवं जोन 10 जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गनिर्देशन और जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा, निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता निरीक्षक गिरीजेश तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक यशवंत बेरिहा एवं अन्य संबंधित जोन 10 स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता टीम के कर्मचारियो की उपस्थिति में जोन 10 क्षेत्र अतर्गत पचपेडी नाका में स्थित केएफसी को औचक निरीक्षण जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने किये जाने पर गदगी पाये जाने किचन का पाईप सीधे सार्वजनिक नाली मे जोडा जाना पाये जाने और केएफसी का कचरा और प्लास्टिक बाहर सार्वजनिक नाली में पाये जाने साथ ही केएफसी को दी गई नोटिस का केएफसी द्वारा कोई जवाब नगर निगम को नहीं दिये जाने और ना ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत कोई भी उचित कार्यवाही करने की स्थिति मिलने पर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्थल पर पहुंचकर निगम स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम जोन 10 स्वास्थ्य विभाग एवं निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग उडनदस्ता की टीम द्वारा कड़ी कार्यवाही कर केएफसी को एसटीपी की व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार नही पाये जाने पर तत्काल सीलबंद कर दिया।

प्रमुख सचिव बोरा अचानकमार क्षेत्र का किया दौरा

बोरा ने की पीएम जनमन और धरती आबा अभियान की समीक्षा

- एटीआर और खुड़िया में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल उन्नयन पर दिया जोर
- शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर दिए निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जिले के लोरमी विकासखण्ड के अचानकमार क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले अचानकमार क्षेत्र स्थित शिवतराई सभाकक्ष में पीएम जनमन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाया जाए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। प्रमुख सचिव ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एटीआर क्षेत्र में होम-स्टे सुविधा विकसित करने तथा खुड़िया में पर्यटन की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही आदिवासी युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने संबंधी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि अचानकमार क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा और कौशल विकास की व्यापक संभावनाएं हैं, जिनका बेहतर उपयोग कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सचिव श्री बोरा ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण से भी जोड़ा जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते

हुए उन्होंने पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ योजनाओं से लाभान्वित करने तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आश्रम एवं छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले सभी स्कूलों और छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में प्रस्तावित विस्थापन की प्रगति, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आवास, पेयजल और अन्य योजनाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी सेवाओं एवं पीवीटीजी बैगा समुदायों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य शासकीय सुविधाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का सर्वे कर विभिन्न योजनाओं का सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सचिव श्री बोरा ने कहा कि पीवीटीजी बैगा समुदाय में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता उन्हें शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने की है। इसके लिए अचानकमार क्षेत्र में लाइब्रेरी सुविधा विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, एसएसपी श्री भोजराम पटेल, डीएफओ श्री अभिनव कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी एसडीएम श्री अजीत पुजारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने ग्राम शिवतराई पहुंचे

प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत शिवतराई पहुंचकर पीएम जनमन योजना के तहत संचालित गतिविधियों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीवीटीजी परिवारों से संवाद कर शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और लाभ की वास्तविक स्थिति जानी। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने पीएम जनमन आवास योजना के हितग्राही श्री रामसिंह बैगा से मुलाकात कर उन्हें मिल रही शासकीय सुविधाओं की जानकारी ली।

पानी के लिए जंगर मासूमों को गोद में लेकर नदी से पानी ढो रहीं महिलाएं, कोपरा पारा के 40 परिवार संकट में

बूंद-बूंद पानी को तरसे ग्रामीणर तपती धूप में नदी तक पैदल जा रहीं महिलाएं, अफसर बना रहे प्रस्ताव

कोंडागांव। एक ओर सरकार गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने और हर घर नल-जल योजना के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुम्हारपारा के कोपरा पारा में ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में यहां की महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर हर दिन चिलचिलाती धूप में आधा से एक किलोमीटर दूर नदी तक पानी भरने जाती हैं। गांव की यह तस्वीर सरकारी योजनाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। दरअसल हाइवे निर्माण के दौरान मेन पाइपलाइन फूट गया था। तभी से समस्या बनी हुई है। करीब 35 से 40 घरों की इस बस्ती में आज तक एक भी शासकीय हैंडपंप नहीं लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से वे पेयजल संकट झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कभी उनकी सुध नहीं ली। गांव में रहने वाली महिलाओं की सुबह पानी की तलाश से शुरू होती है। सिर पर मटका और गोद में बच्चे लिए महिलाएं उबड़ खाबड़ तपती पगडंडी और तेज धूप के बीच नदी तक पहुंचती हैं और वहां से पानी भरकर घर लाती हैं। मजबूरी ऐसी कि कई बार दिन में दो से तीन बार यह दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती में केवल तीन से चार घरों में निजी बोरवेल हैं, लेकिन वहां से पानी लेने के एवज में हर महीने 300 रुपए देने पड़ते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिकांश परिवार इतने पैसे देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें नदी का पानी पीने और दैनिक निस्तार के लिए उपयोग करने मजबूर होना पड़ रहा है। जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

नदी ही एक मात्र सहारा है : ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि दूसरी बस्ती में एक हैंडपंप जरूर लगा है, लेकिन वह काफी दूर है और वहां लगे हैंडपंप का पानी लाल हो जाता है। पानी का रंग और स्वाद खराब होने के कारण वह पीने योग्य नहीं है। ऐसे में नदी ही एकमात्र सहारा बचा है। गर्मी बढ़ने के साथ नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में संकट और गहराने की आशंका है।

पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी पता होता तो शादी नहीं करती : पिंकी चक्रधारी

गोद में 6 माह का बच्चा लेकर पानी भरने पहुंची पिंकी चक्रधारी ने बताया कि गांव में पानी की भारी समस्या है। रोज आधा किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मायके में बोरवेल था, इसलिए इतनी परेशानी कभी नहीं हुई। अगर पहले पता होता कि यहां पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो इस गांव में शादी नहीं करती। पिंकी ने बताया कि महिलाएं पीने के लिए रेत हटाकर झिरिया का पानी निकालती हैं, जबकि नदी के गंदे पानी का उपयोग नहाने और कपड़े धोने में किया जाता है।

राशि नहीं मिली सरपंच

हेम कोर्राम ने बताया कि गांव में पानी संकट गंभीर हो गया है। हाईवे निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने और टंकी मरम्मत के बाद सप्लाई प्रभावित हुई। महिलाएं पानी के लिए भटक रही हैं। राजस्व ग्राम नहीं होने से 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिल रही, जिससे नल-जल और विकास कार्य अटके हैं।

निरीक्षण और प्रस्ताव में अटका विभाग

इस गंभीर समस्या के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल निरीक्षण और प्रस्ताव भेजने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पंचायत और संबंधित विभाग को आवेदन दिया गया, लेकिन न तो कोई स्थायी समाधान निकला और न ही बस्ती में नलकूप खनन का कार्य शुरू हुआ। प्रशासनिक उदासीनता का खामियाजा मासूम बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है।

नलकूल के लिए प्रस्ताव बना रहे है : पीएचई

वीरेंद्र पांडेय, कार्यपालन अभियंता, पीएचई कोण्डागांव ने बताया कि सहायक अभियंता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के बाद एनएच विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में पेयजल समस्या समाधान के लिए नलकूप खनन कराने प्रस्तावा तैयार किया जा रहा है।

कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर में कृषि अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया गया बीजीए उत्पादन एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन का प्रशिक्षण

नारायणपुर। कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग, बीजीए उत्पादन एवं हरी खाद का महत्व विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों तक टिकाऊ एवं कम लागत वाली कृषि तकनीकों को पहुंचाना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखना तथा वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवीके के शस्य विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. हरेंद्र टोंडे ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीजीए उत्पादन एवं हरी खाद के उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेतों में आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और मिट्टी की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है। डॉ. टोंडे ने धान की खेती में बीजीए एवं हरी खाद की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीजीए वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और किसानों की खेती लागत घटती है। उन्होंने कहा कि यदि इन तकनीकों को गांव स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए तो किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किसानों को सरल भाषा में वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। कायक्रम में डॉ. अंकिता सिंह, डॉ. अलिया अफरोज, डॉ. ललित कुमार वर्मा एवं इंद्र कैमरो सहित कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से ग्राम हसलनार के ग्रामीणों को किया जागरूक

कोंडागांव। ग्राम पंचायत हसलनार जिला कोंडागांव (छ.ग.) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी' द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में 'जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा मरकाम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय एवं थाना प्रभारी मर्दापाल सुशील पटेल व अधिकार मित्र सहित ग्रामवासी' उपस्थित रहे। शिविर में संबोधित करते हुए 'प्रधान न्यायाधीश' ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है तथा आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को महिला अधिकार बाल संरक्षण कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण, साइबर अपराध से बचाव, श्रम कानून तथा लोक अदालत के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर 'जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश' ने बच्चों को जानकारी देते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई इसी प्रकार 'सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' के द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शिविर में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति बाल विवाह निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार तथा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में जागरूक किया गया।

न्याय दो या प्राण लो के नारे के साथ बस्तर से रायपुर निकली आदिवासी महिला, संविधान को व्हील चेयर पर रखकर कर रही पदयात्रा

कोण्डागांव। बस्तर जिले की रहने वाली आदिवासी महिला एवं मां दंतेश्वरी की पुजारिन लखमनी बघेल अपनी पैतृक जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर बस्तर से रायपुर तक लगभग 300 किमी की पदयात्रा पर निकली हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले चल रही इस न्याय दो या प्राण लो पदयात्रा के तहत लखमनी बघेल अपने समर्थकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ कोण्डागांव पहुंचीं। इस पदयात्रा की सबसे खास बात यह रही कि पदयात्री दल भारत के संविधान को व्हील चेयर पर रखकर साथ ले जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदर्शनकारी यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आज देश का संविधान विकलांग हो चुका है और आदिवासी समाज को न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तपती गर्मी में नंगे पांव चल रहे पदयात्रियों ने कहा कि वे रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात करेंगे और सीधे उन्हें ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाएंगे। लखमनी बघेल ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्वजों की लगभग 100 एकड़ से अधिक पैतृक भूमि थी, जिसके पुराने रिकॉर्ड और खसरा दस्तावेज आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन वर्तमान में उनकी आधे से अधिक जमीन को नजूल घोषित कर दिया गया है और बाहरी लोगों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार तहसील और प्रशासनिक कार्यालयों में आवेदन देने के बावजूद उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जा करने वालों द्वारा उन्हें लगातार डराया-धमकाया जा रहा है तथा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लखमनी बघेल ने कहा कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं बल्कि एक आदिवासी परिवार के सम्मान, अस्तित्व और अधिकार का सवाल है। मां दंतेश्वरी की पुजारिन होने के बावजूद उन्हें अपनी ही पुश्तैनी जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में मांग की है कि लखमनी बघेल की सम्पूर्ण पैतृक भूमि का निष्पक्ष सीमांकन कराया जाए, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भूमि अधिकार बहाल किए जाएं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। संगठन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो रायपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री निवास के समक्ष शांतिपूर्ण धरना भी दिया जाएगा। पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आजाद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुयल नाग, बस्तर जिलाध्यक्ष आशीष कच्छ, कोण्डागांव जिलाध्यक्ष हेम सिंह मौर्य सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं।

बीजापुर के दूरस्थ वनांचल में सरकार की संवेदनशील पहल, गंगालूर जैसे रिमोट एरिया में कुपोषण मुक्त अभियान की बड़ी सफलता

बीजापुर । प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को बीजापुर जिले में लगातार जमीन पर उतारा जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से अब दूरस्थ अंचलों में भी बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी का प्रेरणादायी उदाहरण है बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र कोटिया पारा का ढाई वर्षीय बालक अरुण हेमला, जिसने सतत देखभाल, सही पोषण और सामुदायिक सहयोग से कुपोषण को मात देकर सामान्य श्रेणी में वापसी की है। यह कहानी केवल एक बच्चे के स्वस्थ होने की नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं, विभागीय प्रतिबद्धता और सामुदायिक सहभागिता की जीवंत मिसाल है। अरुण हेमला, पिता मंगू हेमला एवं माता शर्मीला हेमला का जन्म 21 दिसंबर 2023 को हुआ था। जन्म के समय उसका वजन 2.500 किलोग्राम था। बार-बार बीमार पड़ने तथा घर में पर्याप्त भोजन नहीं कर पाने के कारण उसका वजन लगातार कम बना रहा। अप्रैल 2025 में स्थिति गंभीर होने पर उसे पोषण पुनर्वास केंद्र बीजापुर में भर्ती कराया गया, जहां भर्ती के समय उसका वजन मात्र 8.600 किलोग्राम था, जो उसकी उम्र के अनुसार अत्यंत कम माना गया। पोषण पुनर्वास केंद्र से डिस्चार्ज होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने अरुण के स्वास्थ्य सुधार को मिशन की तरह लिया। पर्यवेक्षक उषा वर्मा के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुमीता सोरी, सहायिका सोनिया माज्जी, मितानिन देवली वाचम एवं ए.एन.एम. शोभा किरण मिंज ने लगातार समन्वित प्रयास किए। टीम ने घर-घर जाकर न केवल बच्चे की निगरानी की, बल्कि परिवार को पोषण, स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति जागरूक भी किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि अरुण घर पर अकेले भोजन नहीं करता था, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में अन्य बच्चों के साथ बैठकर पूरा भोजन कर लेता था। इसके बाद माता-पिता को नियमित रूप से बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र भेजने के लिए प्रेरित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हर सप्ताह बच्चे का वजन लिया गया तथा परिवार को भोजन की थाली में अनाज, दाल, सब्जी और फल जैसे चार रंगों को शामिल करने की जानकारी दी गई। केंद्र में प्रतिदिन गर्म पका भोजन एवं रेडी-टू-ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया गया। साथ ही मितानिन द्वारा दस्त एवं निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए गए। लगातार 13 महीनों तक चले इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया और मई 2026 में अरुण का वजन बढ़कर 10.600 किलोग्राम पहुंच गया। अब वह अपनी उम्र के अनुसार सामान्य श्रेणी में शामिल हो चुका है। उसके चेहरे पर लौटी मुस्कान और आंखों की चमक इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर सही देखभाल से कुपोषण जैसी समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। अरुण की मां शर्मीला हेमला बताती हैं कि पहले उन्हें अपने बेटे की हालत देखकर हमेशा डर लगा रहता था, लेकिन आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार घर पहुंचकर समझाइश दी और बच्चे की देखभाल में सहयोग किया। अब अरुण स्वयं भोजन मांगकर खाता है और पहले से कहीं अधिक सक्रिय एवं स्वस्थ है। पर्यवेक्षक उषा वर्मा ने कहा कि अरुण की सफलता यह साबित करती है कि यदि आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग और मितानिन मिलकर कार्य करें तथा परिवार का सहयोग मिले। तो हर बच्चे को कुपोषण से बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जिले में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीर सावरकर केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही नहीं बल्कि राष्ट्रचेतना, साहस और सामाजिक जागरण के प्रखर प्रतीक थे। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष और तपस्या में समर्पित किया। कठिन परिस्थितियों और यातनाओं के बावजूद उनका राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संकल्प कभी डगमगाया नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर ने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी मुखर होकर आवाज उठाई और सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का सतत प्रयास किया। उनकी लेखनी, विचार और कर्म आज भी देशवासियों को राष्ट्रहित, आत्मगौरव और सामाजिक सदभाव की प्रेरणा देते हैं।

जन्म, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों का मौके पर वितरण, योजनाओं की जानकारी देकर बढ़ाया ग्रामीणों का भरोसा

सुकमा के अंतिम छोर सिंदुरगुड़ा-किस्टाराम तक पहुंचा सुशासन तिहार, आयोग सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

सुकमा। जिले के अतिसंवेदनशील एवं दूरस्थ क्षेत्र सिंदुरगुड़ा और किस्टाराम, जिन्हें सुकमा जिले का अंतिम छोर माना जाता है, वहां आयोजित सुशासन तिहार एवं बस्तर मुन्ने अभियान के विशेष शिविर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। दुर्गम वनांचल में आयोजित इस शिविर ने शासन और ग्रामीणों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम तैयार किया, जहां विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ कई समस्याओं का मौके पर निराकरण भी किया गया। शिविर में पहुंची आयोग सदस्य दीपिका शोरी ने सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पंचायत विभाग के कार्यों की जानकारी ली तथा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए।

दीपिका शोरी ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, कृषि, राशन, आवास सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। आयोग सदस्य ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन तिहार के माध्यम से स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनका निराकरण कर रही है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आम जनता को त्वरित राहत प्रदान करना है।

प्रमाण पत्रों का मौके पर वितरण, ग्रामीणों में दिखी खुशी

शिविर के दौरान जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्रों का मौके पर ही वितरण किया गया। लंबे समय से इन दस्तावेजों की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को शिविर स्थल पर ही प्रमाण पत्र मिलने से उनके चेहरे खिल उठे। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई ताकि ग्रामीण शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।

पीएम आवास निर्माण में तेजी लाने की अपील

आयोग सदस्य दीपिका शोरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों से जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पक्के आवास से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आता है और शासन इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।

गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम ने जोड़ा सामाजिक सरोकारों से

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम भी शिविर का आकर्षण रहा। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में आयोग सदस्य ने सहभागिता करते हुए विभागीय कार्यों की सराहना की।

कई विभागों की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

हालांकि शिविर के दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों की अनुपस्थिति भी देखने को मिली। राशन कार्ड, खाद-बीज एवं कृषि संबंधी जानकारी के लिए पहुंचे ग्रामीण संबंधित अधिकारियों की तलाश करते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि नवीन राशन कार्ड से राशन प्राप्ति, कृषि कार्य हेतु खाद-बीज की उपलब्धता तथा अन्य विभागीय जानकारियों के लिए उन्हें भटकना पड़ा। शिविर में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय उपस्थिति तो रही, लेकिन खाद्य, कृषि तथा कुछ अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इससे कई ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हो सका।

सुशासन तिहार कोई मजाक नहीं, संवेदनशीलता से करें कार्य : दीपिका शोरी

जब ग्रामीणों की शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के कर्मचारियों को बुलाने का प्रयास किया गया और वे उपस्थित नहीं मिले, तब आयोग सदस्य दीपिका शोरी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार कोई मजाक या टाइमपास का कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण विष्णुदेव साय सरकार पर भरोसा करके अपनी समस्याएं लेकर शिविरों में पहुंच रहे हैं। उन्हें शत-प्रतिशत लाभ मिले, यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। केवल उपस्थिति दर्ज कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित होना चाहिए।

शासन और जनता के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी बने सुशासन तिहार

दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिंदुरगुड़ा एवं किस्टाराम में आयोजित यह शिविर इस बात का उदाहरण बने कि शासन अब गांवों तक पहुंचकर सीधे लोगों की समस्याएं सुन रहा है। आयोग सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी की सक्रिय उपस्थिति, ग्रामीणों से सीधा संवाद, प्रमाण पत्रों का वितरण और विभागीय जवाबदेही को लेकर दिए गए स्पष्ट संदेश ने शिविर को प्रभावी बनाया। ग्रामीणों ने भी उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा और शासन की योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार और ग्रामीणों के बीच विश्वास का रिश्ता और अधिक मजबूत होता दिखाई दिया।

एस.आर हॉस्पिटल द्वारा मुख्यमन्त्री कौशल विकास योजना पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सर्टीफिकेट वितरण किया गया

दुर्ग :- एस.आर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर चिखली दुर्ग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पाठ्यक्रम के वर्ष 2025-26 बैच के जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स के उत्तीर्णविद्यार्थियों को सर्टिफ़िकेट प्रदान किया गया ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ के.के.जैन वरिष्ठ चिकित्सक (जनरल फिजीशियन) एवं विशेष अतिथि न्यु प्रेस क्लब ऑफभिलाई के अध्यक्ष अनिल गुप्ता उपस्थित रहे।वहीं अन्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार रमेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार डॉं कमल किशोर शर्मा एवं समाजसेवी विष्णु पाठक ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान संस्था के चेयरमेन द्वारा किया गया।

इस गरिमामय आयोजन में संस्था के चेयरमेन संजय तिवारी ने सर्वप्रथम विद्यार्थीओ को बधाई दी व संस्था के बारे में जानकारी दी कि संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना एवं क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना साथ ही विद्यार्थीयो को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा प्रदान करना है द्ध उन्होंने बताया कि एस.आर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर चिखली दुर्ग में डी.फार्मेसी कोंस एवं पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स व शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मुख्यमन्त्री कौशल विकास योजना के पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है।उन्होंने बताया कि एस.आर ग्रुप के द्वारा सैकड़ों विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात रोजगार भी प्रदान किया गया है।

अतिथि उद्बोधन में डॉ के.के.जैन ने कहा कि कौशल विकास योजना आधारित प्रशिक्षण आज के समय की मांग है एवं विशेष अतिथि अनिल गुप्ता ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एस.आर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यन्त ही सराहनीय है उन्होंने यह भी कहा कि एस.आर हॉस्पिटल द्वारा कौशल विकास योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को दिया गया प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए मिल का पत्थर साबित हो होगा। वरिष्ठ पत्रकार रमेश गुप्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉं कमल किशोर शर्मा एवं समाजसेवी विष्णु पाठक ने भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए बधाई दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुवे अपनी शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर जे.एन.पाण्डेय,अरविन्द खैरवार,विनीता आंचला,नेहा ठाकुर,फ्नीस साहू ,श्रीमती लीना वर्मा व श्रीमती ज्योति दास व शीतल सिन्हा व अस्पताल के अन्य स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन अरविन्द खैरवार ने करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की।

दीपक नगर वार्ड में 36 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन, सड़क और नाली निर्माण से मिलेगी बड़ी राहत

नगर निगम का अधोसंरचना विकास अभियान जारी, वार्ड 23 में होंगे 36 लाख के निर्माण कार्य

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत दीपक नगर वार्ड क्रमांक 23 में नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं आधारभूत अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन महापौर अलका बाघमार द्वारा सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर के उपस्थिति में किया गया। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों की मौजूदगी में लगभग 36 लाख रुपये की लागत से सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई। भूमि पूजन अंतर्गत सड़क नंबर 1 एवं 2 सहित अन्य स्थानों पर नाली निर्माण कार्य 17.50 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क नंबर 4 स्थित अनुप गटागट के सामने 9.66 लाख रुपये की लागत से सीमेंटीकरण कार्य तथा सड़क नंबर 6 में 8.50 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को जल निकासी, आवागमन तथा मूलभूत सुविधाओं में बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में चरणबद्ध रूप से विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। नागरिकों को बेहतर सड़क, नाली एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निगम प्रशासन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बरसात के पूर्व नाली निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नागरिकों को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, शेखर चंद्राकर, वार्ड पार्षद मनोज सोनी, रंजीता पाटिल, लोकेश्वरी ठाकुर, युवराज कुंजाम, मनीष कोठारी, पूर्व पार्षद मीना सिंह,विजय जलकारे, अरुण सिंह, कार्यपालन अभियंता मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, उप अभियंता अर्पणा मिश्रा सहित वार्ड के नागरिकगण उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक, ग्रीष्मकालीन मौसमी बीमारी की रोकथाम पर की गई रायशुमारी

दुर्ग। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए सभी स्तरों पर स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी को सशक्त करने एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु ज़िला कार्यबल पर्यावरण स्वास्थ्य प्रकोष्ठ समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ग्रीष्मकालीन मौसमी बीमारी की रोकथाम पर रायशुमारी की गई। बैठक में आई.डी.एस.पी. दुर्ग के नोडल अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे ने लू व तापघात के लक्षण और बचाव के उपाय पर विस्तार से प्रकाश डाला।

गर्मी से संबंधित बीमारी के लक्षण - बेहोशी। मांसपेशियों में जकड़न। मिर्गी / दौरा पड़ना। चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, अधिक पसीना आना। कमजोरी / चक्कर आना। सांस और दिल की धड़कन तेज होना।

बचाव -पर्याप्त तरल पदार्थो को लें। अपने आप को अच्छे से ढकें। धूप में खेलने से बचे। गाड़ी लॉक ना करे जब बच्चे गाड़ी में हों।

प्राथमिक चिकित्सा के उपाय -बच्चे को तुरंत अंदर या छांव में लाएं। बच्चों के कपड़ों को जहां तक हो सके ढीला कर दे। नल के पानी से पोंछा करें या छिड़काव करें। अगर बच्चे को उल्टियां हों, तो उसे करवट के बल लिटाएं ताकि गले में कुछ ना फंसे।

क्या करें -पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, भले ही आपको प्यास न लगी हो। यात्रा करते समय या जब भी बाहर जायें तो पीने का पानी साथ रखें। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओ.आर.एस.) का उपयोग करें, और घर के बने पेय जैसे नींबू पानी, छाछ / लस्सी का सेवन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां खाएं जैसे-तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास, ककड़ी, सलाद या अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध फल और सब्जियां। ढीले, सूती वस्त्र पहनें, कोशिश करें कि हल्के रंग के कपड़े पहनें। अपने सिर को ढकें-धूप के सीधे संपर्क में आने के दौरान छाता, टोपी, तौलिया और अन्य पारम्परिक टोपी/गमछा का उपयोग करें।

क्या न करें -कोशिश करें कि धूप में न निकलें, खासकर दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच। दोपहर में बाहर होने पर शारीरिक और थका देने वाली गतिविधियों से बचने की कोशिश करें। चरम गर्मी के घंटों के दौरान खाना पकाने से बचें।

लू के लक्षण दिखने पर मितानिन, ए.एन.एम. से ओ.आर.एस. के पैकेट हेतु संपर्क करें यथाशीघ्र किसी नजदीकी चिकित्सा केन्द्र में उपचार हेतु ले जाएँ। इस हेतु नगरीय निकाय एव शुद्ध पेयजल हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से निरंतर समन्वय बनाया जा रहा है। मितानिन व संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में दवाईयों उपलब्ध करा दी गयी है।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर मती योगिता देवांगन, जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली आयुक्त मती मोनिका वर्मा, नगर निगम चरोदा आयुक्त दशरथ राजपूत, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, संयुक्त कलेक्टर सिल्ली थॉमस, एसडीएम धमधा सोनाल डेविड, एसडीएम भिलाई 3 महेश राजपूत, डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनसमस्या निवारण शिविर के माध्यम से कौशल्या गौड़ को मिली श्रवण यंत्र की सौगात

कौशल्या के जीवन में फिर लौटी खुशियों की गूंज

दुर्ग। सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत लगने वाले शिविरों की कड़ी में विगत 23 मई को दुर्ग शहर के पुराना गंज मंडी प्रांगण में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर कई परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इसी कड़ी में, वार्ड क्रमांक 26 संतरा बाड़ी की निवासी मती कौशल्या गौड़ भी अपनी समस्या के समाधान की आस लेकर इस शिविर में शामिल हुई। कौशल्या लंबे समय से सुनने की गंभीर समस्या (श्रवण बाधिता) से जूझ रही थीं, जिसके कारण उनका दैनिक जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। आसपास की बातें और अपनों की आवाजें स्पष्ट न सुन पाने के कारण वे सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर लगातार एकाकीपन और परेशानियों का सामना कर रही थीं। इस शारीरिक असमर्थता का कोई स्थाई समाधान नहीं मिल पा रहा था। सुशासन तिहार शिविर ने उनकी इस वर्षों पुरानी तकलीफको चंद मिनटों में दूर कर दिया। शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने कौशल्या जी की समस्या को बेहद गंभीरता से सुना और तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव के हाथों कान की मशीन प्रदान की। आधुनिक श्रवण यंत्र की सहायता से अब वे स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम हो गई हैं, जिससे उनके जीवन में पुनः सकारात्मक बदलाव आया है। इस त्वरित समाधान से गदगद कौशल्या गौड़ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का सहृदय आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जमीनी स्तर पर लगाए जा रहे ये शिविर आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

सुशासन तिहार समाधान शिविर में 117 आवेदन का निराकरण

अम्लेश्वर पालिका में विष्णु के सुशासन में हो रहा समस्या का समाधान

अमलेश्वर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की जनकल्याणकारी नीति और विकास परख सोंच को साकार करने दुर्ग जिले के नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में सुशासन तिहार मनाया गया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव के दिशा निर्देश व दुर्ग सांसद विजय बघेल के मार्ग दर्शन में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में दिनांक 04, 09 एवं 26 मई 2026 को विभिन्न वार्डो में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी विभागों के कुल 295 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 261 आवेदन विभिन्न मांग एवं 34 शिकायत प्राप्त हुई है। कुल 117 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। शेष प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण कर उन्हें सम्बंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है। शिविर में शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लर्निंग लायसेंस, श्रम कार्ड, आभा कार्ड, राशन कार्ड का तत्काल निराकरण किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को सुपोषण कीट का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जनों का स्वास्थ्य परिक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। शिविर में जिला प्रशासन की ओर से एडीएम योगिता देवांगन एवं एसडीएम लवकेश ध्रुव द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया। इन जनसमस्या निवारण शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष दयानंद सोनकर, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, पीआईसी सदस्य एवं सम्बंधित वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। शिविर के नोडल अधिकारी प्रीति गुप्ता मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ढालेंद्र कुमार ठाकुर उप अभियंता, नगर पालिका कर्मचारी एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी की उपस्थित रही।

जनपद सदस्य पद हेतु भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र साहू को मिल रहा जबरदस्त जनसमर्थन, कार्यकर्ताओं ने तेज किया जनसंपर्क अभियान

पाटन-अमलेश्वर। जनपद पंचायत पाटन क्षेत्र क्रमांक-04 के उपचुनाव में जनपद सदस्य पद के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र साहू को क्षेत्र में जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता लगातार डोर-टू-डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र साहू भी भीषण गर्मी और दोपहर की तपिश के बीच घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। इस दौरान मतदाताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन पर मुहर लगाने की अपील की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों से लेकर संसद तक भाजपा की सरकार को मजबूत कर विकास की गति को और तेज करने का संदेश दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत के युवा सरपंच रवि सिंगौर भी कड़ी धूप में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से ट्रिपल इंजन सरकार को मजबूत बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र साहू के चुनाव चिन्ह झोपड़ी छाप पर मुहर लगाने की अपील की। मीडिया से चर्चा करते हुए रवि सिंगौर ने कहा कि सांकरा और पाहंदा के मतदाता सुरेंद्र साहू को अपना जनपद सदस्य बनाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार दोनों गांवों की तस्वीर बदलने का काम करेगी। इसलिए मतदाता झोपड़ी छाप पर मुहर लगाकर सुरेंद्र साहू को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव प्रभारी हर्षा चंद्राकर एवं नेताओं के निर्देशन में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। निश्चित रूप से 1 जून को क्षेत्र की जनता झोपड़ी छाप पर मुहर लगाकर सुरेंद्र साहू को भारी मतों से विजयी बनाएगी।

और क्षेत्र के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

सखी निवास के प्रबंधक, वार्डन एवं केयर टेकर पदों की भर्ती के लिए शुद्धि पत्र जारी, दावा-आपत्ति 3 जून तक आमंत्रित

दुर्ग। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग द्वारा 'मिशन शक्ति' योजना के अंतर्गत संचालित 'सखी निवास' में पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अधिकारिक सूचना (शुद्धि पत्र) जारी की गई है। इस संशोधित अधिसूचना के माध्यम से पूर्व में जारी विज्ञापन की शर्तों में आंशिक बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सखी निवास में प्रबंधक, वार्डन एवं केयर टेकर के पदों पर भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन में पदों को आरक्षण नियम के अनुसार 'आरक्षित' किया गया था। शासन के नए निर्देशानुसार, उक्त पद सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) के होने के कारण इनमें आरक्षण नियम का पालन किया जाना अनिवार्य नहीं है। अतः शासन के निर्देशों के परिपालन में विज्ञापित आरक्षित पदों को अब 'अनारक्षित' किया गया है। साथ ही, विज्ञापन में उल्लिखित 'सखी निवास के संविदा पदों' के स्थान पर अब इसे 'सखी निवास के सेवा प्रदाता के पदों' पर नियुक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा यह शुद्धि पत्र जारी किया गया है। भर्ती से जुड़े संशोधित नियमों के संबंध में यदि किसी भी आवेदक को कोई आपत्ति हो, तो वे विज्ञापन प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर अपनी दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 03 जून 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक अपनी दावा-आपत्ति स्पीड पोस्ट, ई-मेल, कोरियर के माध्यम से या फिर स्वयं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग) में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस 'शुद्धि पत्र' का विस्तृत अवलोकन जिले की आधिकारिक वेबसाइट 222.स्रहृद्द.द्दश1.द्बठ्ठ एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी के सूचना पटल (नोटिस बोर्ड) पर किया जा सकता है।

दिव्यांग संतोष के जीवन में आई आत्मनिर्भरता की नई सुबह

सुशासन शिविर में मिली बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल

दुर्ग। सुशासन संकल्प को धरातल पर चरितार्थ करने के उद्देश्य से पूरे जिले में 'सुशासन तिहार 2026' के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक सुगमता और लोक-कल्याण को समर्पित इस अभियान के तहत विगत 22 मई को दुर्ग जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम बेलौदी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर कई जरूरतमंदों के लिए संबल और खुशियों का माध्यम बना, जहां जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक दिव्यांग हितग्राही को बड़ी राहत पहुंचाई गई। ग्राम नागपुरा निवासी दिव्यांग संतोष कुमार ठाकुर (पिता दशरू राम ठाकुर) लंबे समय से शारीरिक दिव्यांगता के कारण चलने-फिरने में असमर्थ थे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से परिजनों अथवा आस-पास के लोगों पर निर्भर थे। जब उन्होंने शिविर में अपनी इस व्यावहारिक कठिनाई को अधिकारियों के समक्ष रखा, तो जिला प्रशासन द्वारा तत्काल औपचारिकताएं पूर्ण कर उनके लिए बैटरी चालित ट्राईसाइकिल स्वीकृत की गई। शिविर के दौरान मुख्य अतिथि दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के कर-कमलों से संतोष कुमार ठाकुर को यह आधुनिक बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। विधायक चंद्राकर ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन तिहार का मूल लक्ष्य ही यही है कि कोई भी पात्र हितग्राही व्यवस्था की कमियों के कारण शासन की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के उपरांत भावुक स्वर में संतोष कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस त्वरित सहायता से अब वे बिना किसी मानवीय सहारे के गरिमापूर्ण ढंग से आवागमन कर सकेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2026 मतदान दलों को दिया गया सघन प्रशिक्षण

दुर्ग। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में आज बी.आई.टी. दुर्ग के मैकेनिकल हॉल में जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा एवं पाटन के लिए गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनपद पंचायत दुर्ग के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान दलों को निर्वाचन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला मास्टर ट्रेनर भुवाल द्वारा मतदान दलों को मतदान केंद्र की स्थापना, मतपत्रों की व्यवस्था तथा मतदान के पश्चात आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करने के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मतदान कर्मियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया ताकि मतदान दिवस पर कोई तकनीकी या व्यावहारिक समस्या न हो।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995